सब का सपना

निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र

अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण का हुआ समापन, मूल्यांकन में परखी पेज: 4

ट्रोलिंग को सफलता की कहानी का हिस्सा मानती पेज: 8

वर्ष : 02 | अंक : 148 | बुधवार 02 सितंबर 2026 | अमरोहा (उत्तर प्रदेश) | www.sabkasapna.com | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2 रुपए

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की भतीजी बीरभूम में मृत मिलीं, डिप्रेशन-नौकरी छूटने से गहराया था तनाव

नई दिल्ली एजेंसी: पुलिस ने मंगलवार को बताया कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की भतीजी पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अपने घर पर मृत पाई गईं। मंगलवार दोपहर रामपुरहाट के कुसुम्बा गांव में 31 साल की महिला का शव उसके घर की दूसरी मंज़िल के एक कमरे में मिला। मृतक महिला ममता के चचेरे भाई की बेटी थी। परिवार वालों ने बताया कि वह पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था। परिवार वालों ने यह भी बताया कि कथित भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी नौकरी चली गई थी। अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटना की जांच चल रही है।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की पहल, 17 सितंबर से एक महीने चलेगा सेवा संकल्प अभियान

नई दिल्ली एजेंसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा देशभर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा, जनकल्याण और जनसंपर्क गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। अभियान के तहत देशभर में विभिन्न सेवा कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों का आयोजन किया जाएगा। वाडनगर और काशी से निकलेंगी जनसंपर्क यात्राएं भाजपा अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वाडनगर और कर्मभूमि काशी वाराणसी से विशेष जनसंपर्क यात्राएं निकालेगी। दोनों शहरों से रवाना होने वाली टीमें देश के

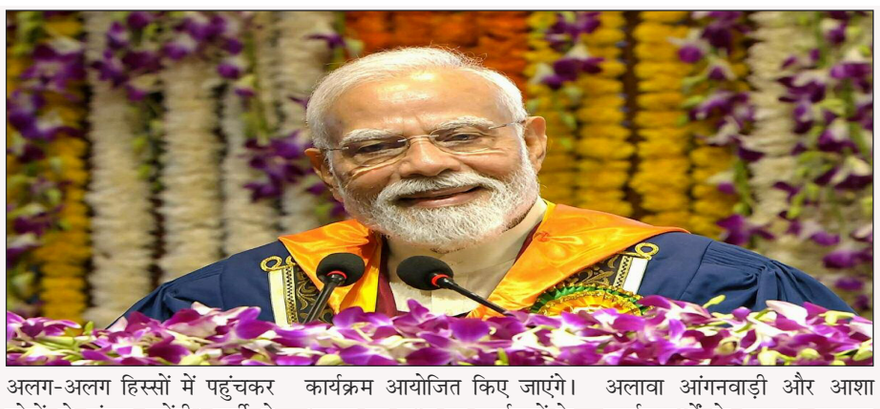

अलग-अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगी। पार्टी ने वाडनगर से काशी तक यात्रा के साथ-साथ व्यापक जनसंपर्क की रणनीति तैयार की है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशा में होंगे कार्यक्रम अभियान के दौरान देश की उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशाओं में भी रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा का लक्ष्य इन कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाना है। रक्तदान से लेकर स्वास्थ्य जांच तक कार्यक्रम एक महीने तक चलने वाले अभियान में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम भी होंगे। नमो सेवा गाथा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों से जुड़े पहलुओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भाजपा

इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान.....

एक महीने तक चलने वाले अभियान में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम भी होंगे।

अभियान के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए विशेष शिविर लगाएगी। इन शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और पात्र लाभार्थियों को उनका लाभ दिलाने पर जोर रहेगा। युवाओं को जोड़ने पर भी जोर अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत राष्ट्रीय युवा पहल चुनौती समेत अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अभियान से जोड़ने की योजना है। तीन तारीखों पर विशेष आयोजन भाजपा ने अभियान के दौरान तीन तारीखों को विशेष महत्व दिया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे होने का अवसर है। इन तीनों अवसरों पर विशेष सेवा और जनकल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में सरकार और संगठन मिलकर चलाएंगे अभियान दिल्ली में सेवा संकल्प अभियान दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जाएगा। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में आयोजित बैठक में अभियान की रूपरेखा जारी की गई। सेवा और जनसंपर्क पर भाजपा का फोकस भाजपा के अनुसार, अभियान के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ सेवा गतिविधियों का भी व्यापक आयोजन किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जनकल्याण के संदेश से जोड़ते हुए यह अभियान समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने

खटीमा गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को किया नमन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद स्मारक, खटीमा में राज्य निर्माण आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किया है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। अमर शहीदों के सपनों और आकांक्षाओं के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और नए उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने

मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत भावुक दिन है, क्योंकि हम उन लोगों को दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने हमारे राज्य को बनाने के आंदोलन में अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं। यह दिन हमें उस संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिसकी वजह से हमारा नया राज्य बना। यह उन बहादुर बेटों और आंदोलनकारियों को याद करने का दिन है जिन्होंने एक अलग उत्तराखंड का सपना देखा था और उस सपने को सच करने के लिए अपने सभी निजी मोह-माया को पीछे छोड़ दिया। मैं उन सभी के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं। मैं खटीमा की दिल दहला देने वाली घटना को याद करता हूं और हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में योगदान दिया। सिटी पार्क (ऑक्सीजन पार्क) का उद्घाटन करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि यह ऑक्सीजन पार्क खटीमा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हमारे लोगों, पर्यटकों और महिलाओं के घूमने-फिरने और समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह होगी। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, जब पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। खटीमा गोलीकांड उत्तराखंड के इतिहास की वह पीड़ादायक घटना है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना ने राज्य निर्माण के आंदोलन को नई दिशा दी थी।

जीडीपी ग्रोथ पर खरगे का तंज: सरकार पीआर में व्यस्त, देश में बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति चरम पर

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जब उन्होंने 7.8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ रेट की तारीफ की। खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम नागरिकों की आर्थिक चुनौतियों को छिपाने के लिए पब्लिक रिलेशंस का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स पर एक बयान में, खड़गे ने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को लाइट्स, कैमरा और इनएक्शन बताया। उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स (अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने के आंकड़े) को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रही है, वहीं आम आदमी अब भी तीन यू से जूझ रहा है – अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय

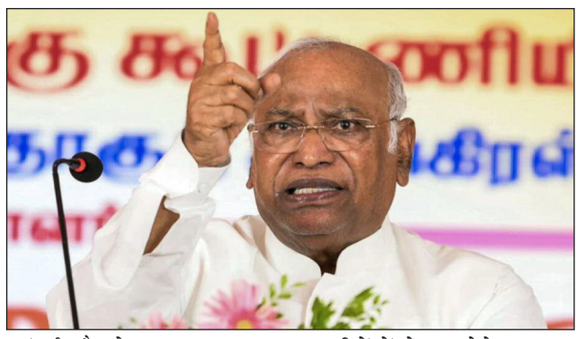

महंगाई और बेलगाम असमानता। खड़गे ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और दावा किया कि लगभग 40% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। उन्होंने आगे आंकड़े देते हुए कहा कि जुलाई 2026 तक, 15 से 29 साल की उम्र के हर छह भारतीयों में से एक बेरोजगार था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के पुराने वादे पर भी निशाना साधा और कहा कि यह वादा पूरी तरह से टूट गया है। खड़गे ने जरूरी चीजों की कीमतों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने खुदरा महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाना पकाने का तेल, चावल और दूध जैसी रोजमर्रा की रसोई की चीजों की कीमतें घरों के बजट पर दबाव डाल रही हैं। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि बढ़ते खर्चों की वजह से आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। आर्थिक असमानता के मुद्दे पर खड़गे ने आरोप लगाया कि भारत में अमीरी-गरीबी का अंतर काफी बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास है, जबकि सबसे गरीब 50% लोगों के पास सिर्फ 15% संपत्ति है। उन्होंने इस असमानता के लिए

एससी से छात्रों को बड़ी राहत ! सरकार ने प्राथमिकी रद्द करने के फैसले का किया स्वागत, नड्डा बोले- छात्रों का भविष्य प्राथमिकता

नई दिल्ली एजेंसी: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें देश भर में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज सभी प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा 5 सितंबर को अपना मार्च वापस लेने के बाद आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, नड्डा ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार शिक्षा सुधारों को लेकर सीजेपी की सभी मांगों को पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नड्डा ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमने भारत सरकार की ओर से भरोसा दिलाया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे और भविष्य में उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी क्रम में, हमने बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों से भी बातचीत की और अब हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। इससे पहले नीट परीक्षा विवाद

को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ देश भर में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की राज्य की छूट बनी रहेगी। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि उसके ये निर्देश फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी लंबित संवैधानिक चुनौती पर कोई असर नहीं डालेंगे। शुरूआत में, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार विरोध-प्रदर्शन की उन खास घटनाओं से जुड़ी प्राथमिकी पर आगे नहीं बढ़ेगी और उन्हीं घटनाओं के लिए कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मुआवजे के अपने वादे पर कायम है और राज्यों व अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करके मुआवजे के तौर-तरीके तय किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, डाक से भेजी गई चिट्ठी

बिहार एजेंसी: खबरों के मुताबिक, मंगलवार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को डाक से आए एक पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। पत्र में चेतावनी दी गई थी कि उन्हें जल्द ही कट्टर आतंकवादी मार डालेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री के ऑफि स ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को इस धमकी के बारे में जानकारी दी है और उचित कार्रवाई की मांग की है। खबरों के मुताबिक, यह चिट्ठी मंत्री के ऑफिस को मिल गई है और जरूरी सुरक्षा इंतजामों और जांच के लिए इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दे दी गई है। चिट्ठी भेजने वाले या उसके स्रोत के बारे में फि लहाल कोई और जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें डाक से जो पत्र मिला, उसे भेजने वाले के बारे में जानकारी, उसे कहाँ से पोस्ट किया गया था और क्या इस धमकी का संबंध किसी ज्ञात व्यक्ति या संगठन से है - इन बातों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पत्र की सामग्री और उपलब्ध अन्य सबूतों की जाँच करके धमकी की विश्वसनीयता और उसके स्रोत का पता लगाने की उम्मीद है। यह पहली बार नहीं है जब पासवान को ऐसी धमकी मिली है।

इससे पहले जुलाई 2025 में, जब उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। बताया जाता है कि यह धमकी एक इंस्टाग्राम अकाउंट से दी गई थी, जिसके बाद एलजेपी(आर) के एक प्रवक्ता ने पटना साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

देशभर में पेपर लीक प्रदर्शन की प्राथमिकी रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 का उपयोग

नई दिल्ली एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दीं, जिन्होंने कथित पेपर लीक के खिलाफ हाल ही में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा पारित इस आदेश में दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 से 25 जुलाई के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में हजारों छात्रों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। कोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की थीं। सीजेआई ने कहा कि 20 से 25 जुलाई तक, हजारों छात्रों ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में विरोध प्रदर्शन

में हिस्सा लिया। पुलिस ने कुल 13 प्राथमिकी दर्ज कीं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली पुलिस उन 2,873 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस उन 2,873 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया जाए। चीफ जस्टिस ने संकेत दिया कि कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश के दायरे में आने वाले छात्रों के खिलाफ सिर्फ. इसलिए कोई और कार्रवाई न हो कि कोई प्राथमिकी कोर्ट के ध्यान में नहीं लाई गई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर किसी राज्य में कोई ऐसी प्राथमिकी है जिसकी जानकारी हमारे सामने नहीं लाई गई है

सीएम विजय ने खोला मेट्टूर बांध, कहा- कावेरी जल तमिलनाडु का कानूनी अधिकार, कर्नाटक को दी कड़ी चेतावनी

नई दिल्ली एजेंसी: कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक के साथ चल रहे विवाद के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने का आदेश दिया, ताकि पीने के पानी की जरूरतें पूरी हो सकें और कावेरी डेल्टा में सांबा की खेती हो सके। उन्होंने मंगलवार सुबह सलेम में पानी छोड़ा। हालांकि, विजय ने कहा कि कावेरी नदी का पानी - जो दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है - तमिलनाडु का "कानूनी अधिकार" है। यह अधिकार कावेरी ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी, 2018 के फैसले के तहत मिला है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, विजय ने कहा हम किसी भी हाल में यह अधिकार नहीं छोड़ेंगे। सरकार तमिलनाडु का वाजिब हिस्सा दिलाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु को पानी छोड़ने के संबंध में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के निदेर्शों का पालन सुनिश्चित करे। साथ ही, कोर्ट ने यह देखने के लिए एक हफ़्ते और इंतजार करने का फैसला किया कि क्या राज्य पानी के बंटवारे के आदेश का पालन करना

जारी रखता है। मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय के कार्यालय ने कहा कि मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की हर एक क्यूबिक फीट मात्रा का इस्तेमाल

मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय के कार्यालय ने कहा कि मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की हर एक क्यूबिक फीट मात्रा का इस्तेमाल किसानों के फायदे के लिए किया जाएगा।

किसानों के फायदे के लिए किया जाएगा। साथ ही, अधिकारी पानी की अनधिकृत निकासी पर सख़्त कार्रवाई करेंगे, जिसमें कावेरी नदी और उसकी नहरों से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए पानी निकालना भी शामिल है। जो लोग अधिकृत पंपिंग योजनाओं के तहत तय मात्रा से ज्यादा पानी निकालेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मेट्टूर बांध में 54.452 टीएमसी पानी जमा है, जलस्तर 91.56 फीट है और पानी का बहाव (इनफ्लो) 10,857 क्यूसेक दर्ज किया गया है। सरकार बांध में जमा पानी और बहाव पर कड़ी नजर रखेगी और सिंचाई की जरूरतों के आधार पर चरणों में पानी छोड़ेगी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पानी की सप्लाई का सही तरीके से मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण, जल संसाधन, और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों को संबंधित ज़िला प्रशासनों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। इन उपायों को लागू करने के लिए, जल संसाधन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों, पुलिस और टैंज-डको के अधिकारियों की संयुक्त टीमें तैनात की जाएंगी। ये टीमें पानी की अवैध निकासी को रोकने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी करेंगी। इस बीच, राज्य सरकार कावेरी के पानी में तमिलनाडु के हिस्से को सुरक्षित रखने और डेल्टा क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है और कानूनी व प्रशासनिक कदम उठा रही है।

संपादकीय

फिर-फिर निर्भया कांड

एक बार फिर बारह साल पुराने निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। निर्भयाकांड में दिसंबर 2012 में 23 साल की युवती के साथ क्रूरता से गैंगरेप हुआ था, जिसकी बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देश में व्यापक आक्रोश उभरा था। यौन हिंसा के खिलाफ कानून कठोर किए गए। इस कांड में साल 2020 में चार अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्त कानून और कठोर सजाओं के बाद ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा? दुखद है कि एक बार फिर निर्भयाकांड की पुनरावृत्ति हुई । अकेली नाबालिग लड़की, खाली बस और चलती बस में चालक-परिचालक द्वारा गैंग रेप। उ.प्र. की एक सोलह साल की लड़की किसी बात पर मां की डांट से क्षुब्ध हो घर छोड़कर अपने रिश्तेदार से मिलने नोयडा सेक्टर-63 के लिये चली। लेकिन रात के अंधेरे और बारिश के मौसम की गफलत में नोयडा के परी चौक पर उतर गई। सेक्टर-63 जाने के लिये उसने जिस बस को रुकवाया, उसमें बैठे दरिंदों ने बस के वहीं जाने की बात कहकर उसे बैठा लिया। पर्दे लगी स्लीपर बस में लड़की के बैठते ही परिचालक ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। चालक-परिचालक ने दुराचार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 47 किलोमीटर के सफर में उसके साथ यौन हिंसा हुई। अपराधी उसे कश्मीरी गेट के निकट रिंग रोड में छोड़कर फरार हो गए। किशोरी ने साहस दिखाते हुए रात ही में कश्मीरी गेट पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में टीम बनाकर पड़ताल की। बस की पहचान व रूट की जानकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिये की गई। चालक-परिचालक को तिमारपुर की बस पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। फोरेंसिक जांच के लिये बस को भी कब्जे में लिया गया है। लेकिन सवाल है कि चार अगस्त की घटना को पुलिस ने क्यों पर्दे में रखा? आखिर क्यों हादसे की सार्वजनिक जानकारी 31 अगस्त को मीडिया को दी गई?

चिंतन-मनन

मन की शक्ति

मन को जीवन का केंद्रबिंदु कहना असंभव नहीं है। मनुष्य की क्रियाओं, आचरणों का प्रारंभ मन से ही होता है। मन तरह-तरह के संकल्प, कल्पनाएं करता है। जिस ओर उसका रुझान हो जाता है उसी ओर मनुष्य की सारी गतिविधियां चल पड़ती है। जैसी कल्पना हो उसी के अनुरूप प्रयास-पुरुषार्थ एवं उसी के अनुसार फल सामने आने लगते हैं। मन जिधर रस लेने लगे उसमें लौकिक लाभ या हानि का बहुत महत्व नहीं रह जाता। प्रिय लगने वाले के लिए सब कुछ खो देने और बड़े से बड़े कष्ट सहने को भी मनुष्य सहज ही तैयार हो जाता है। मन यदि अच्छी दिशा में मुड़ जाए; आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास में रुचि लेने लगे तो जीवन में एक चमत्कार हो सकता है। सामान्य श्रेणी का मनुष्य भी महापुरुषों की श्रेणी में आसानी से पहुंच सकता है। सारी कठिनाई मन को अनुपयुक्त दिशा से उपयुक्त दिशा में मोड़ने की ही है। इस समस्या के हल होने पर मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य बनता हुआ देवत्व के लक्ष्य तक सुविधापूर्वक पहुंच सकता है। शरीर के प्रति कर्तव्य पालन करने की तरह मन के प्रति भी हमें अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना चाहिए। कुविचारों और दुर्भावनाओं से मन गंदा, मलिन और पतित होता है, अपनी सभी विशेषता और श्रेष्ठताओं को खो देता है। इस स्थिति से सतर्क रहने और बचने की आवश्यकता का अनुभव करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मन को सही दिशा देते रहने के लिए स्वाध्याय की वैसी ही आवश्यकता है जैसे शरीर को भोजन देने की। आत्मनिर्माण करने वाली जीवन की समस्याओं को सही ढंग से सुलझाने वाली उत्कृष्ट विचारधारा की पुस्तकें पूरे ध्यान, मनन और चिंतन के साथ पढ़ते रहना ही स्वाध्याय है। यदि सुलझे हुए विचारों के जीवन विद्या के ज्ञाता कोई संभ्रांत सज्जन उपलब्ध हो सकते हों तो उनका सत्संग भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मन का स्वभाव बालक जैसा होता है, उमंग से भरकर वह कुछ न कुछ करना-बोलना चाहता है। यदि दिशा न दी जाए तो उसकी क्रियाशीलता तोड़-फोड़ एवं गाली-गलौज के रूप में भी सामने आ सकती है। मन में जब सद्विचार भरे रहेंगे तो कुविचार भी कोई दूसरा रास्ता टटोलेंगे। ...

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह : जंक फूड की चमक के पीछे छिपता पोषण का संकट

योगेश कुमार गोयल

भारत में प्रतिवर्ष लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से एक से 7 सितम्बर के बीच 'राष्ट्रीय पोषण सप्ताह' मनाया जाता है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और पोषण बोर्ड प्रतिवर्ष एक विशेष थीम के साथ इसका आयोजन करता है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2026 के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय है 'पोषण की शक्ति को जानें' जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देने और कुपोषण को रोकने के लिए सभी आयु समूहों के लिए संतुलित आहार और स्वस्थ खाने के महत्व पर जोर देता है। दरअसल स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार के सेवन की आवश्यकता है लेकिन आज की बिगड़ी जीवनचर्या और गलत खानपान के कारण लोगों में तरह-तरह की बीमारियां पनप रही हैं। एक स्वस्थ और संतुलित आहार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को पोषण प्रदान करता है और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पोषण सप्ताह के अवसर पर बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों को शरीर को पोषण देने वाली खानपान की चीजों के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दरअसल स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत द्वारा बेहतर कार्य करने के बावजूद लोगों में सेहत को लेकर जागरूकता के अभाव के चलते रोगियों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत भारी पड़ रहा है। पोषण के महत्व को समझते हुए लोगों को खानपान, पोषण की पूर्ति और सेहत को लेकर जागरूक करने के लिए मार्च 1975 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाए जाने की घोषणा सर्वप्रथम 'अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन' द्वारा की गई थी, जिसे अब 'न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस एकेडमी' के नाम से जाना जाता है। 1980 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक सप्ताह के बजाय पूरे एक माह तक मनाया जाने लगा लेकिन 1982 में निर्णय लिया गया कि इसे पूरे एक महीने के बजाय सितम्बर महीने के पहले सप्ताह में ही मनाया जाएगा। तभी से एक से सात सितम्बर तक 'राष्ट्रीय पोषण सप्ताह' मनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह के अवसर पर लोगों को शरीर को पोषण देने वाले फल, सब्जियों और अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्रियों को आजमाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुपोषण का मनुष्य के स्वास्थ्य और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी और आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या भी उत्पन्न होती है। पोषण स्वास्थ्य और कल्याण का केन्द्र बिंदु है, जो कार्य करने के लिए शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करता है और तंदुरुस्त एवं बेहतर महसूस करने में भी मददगार होता है। पर्याप्त पोषण का सेवन करने वाले व्यक्ति अधिक कार्य करते हैं जबकि खराब पोषण प्रतिरक्षा में कमी, बीमारी के जोखिम को बढ़ाने, शारीरिक एवं मानसिक विकास को क्षीण करने तथा कार्यक्षमता में कमी पैदा करने का कार्य करता हैं।

कानून का डर ही नहीं, संस्कारों की रोशनी भी जरूरी

कांतिलाल मांडोत

नाबालिग छात्रा के साथ बस में अपराध समाज के लिए चेतावनी, बेटियों की सुरक्षा केवल कड़े कानून से नहीं बल्कि चरित्र निर्माण से होगी...

नई दिल्ली में 16 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस में हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। पुलिस के अनुसार छात्रा ग्रेटर नोएडा के परी चौक से एक बस में सवार हुई थी और बाद में उसे दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छोड़ दिया गया। मामले में बस चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया गया है। घटना की जांच चल रही है और अदालत में आरोपों की पुष्टि तथा अंतिम दोष सिद्ध होना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि एक नाबालिग लड़की के साथ इस प्रकार की कथित घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कानून कड़े होने के बावजूद अपराधियों के मन में कानून का भय क्यों नहीं पैदा हो रहा है? देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कठोर प्रावधान मौजूद हैं। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया है और गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो स्पष्ट होता है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। कानून आवश्यक है, लेकिन अपराध रोकने के लिए कानून के साथ सामाजिक चेतना, नैतिक शिक्षा, परिवार के संस्कार और जिम्मेदार नागरिकता भी उतनी ही आवश्यक है।

यह घटना इसलिए भी चिंता बढ़ाती है क्योंकि पीड़िता एक छात्रा है। वह किसी सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रही एक बच्ची है। परिवार से किसी बात को लेकर निकली, रास्ते में परिस्थितियों के कारण असहाय हुई और जिस वाहन को उसने मदद का माध्यम समझा, उसी में उसके साथ कथित अपराध हो गया। यह स्थिति बताती है कि सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए।

सार्वजनिक परिवहन में चालक और परिचालक केवल वाहन चलाने या यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले कर्मचारी नहीं होते। उनके ऊपर यात्रियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए परिवहन कंपनियों और संबंधित विभागों को कर्मचारियों के सत्यापन, प्रशिक्षण और निगरानी को गंभीरता से लेना चाहिए। बसों में पर्याप्त निगरानी व्यवस्था, आपातकालीन सहायता, शिकायत तंत्र और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए। किसी भी यात्री को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि संकट की स्थिति में वह पूरी तरह अकेला है।

लेकिन सवाल केवल व्यवस्था का नहीं है। सवाल उस मानसिकता का भी है जिसमें किसी लड़की या महिला को कमजोर समझकर उसके साथ मनमानी करने की कोशिश की जाती है। किसी महिला की मजबूरी, अकेलापन या असहाय स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने का अधिकार नहीं देती। किसी की चुप्पी को सहमति समझना, विरोध को दबाने की कोशिश करना या डराकर अपनी बात मनवाना घोर अन्याय है। यह बहादुरी नहीं, बल्कि कायरता और चरित्रहीनता है। समाज को यह समझना होगा कि महिलाओं के सम्मान की शुरूआत घर से होती है। बच्चे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस वातावरण में बड़े होते हैं, इसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माता-पिता द्वारा दिए गए संस्कार जीवनभर साथ रहते हैं। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना जरूरी है कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। लड़की और लड़के में भेद किए बिना दोनों को मयार्दा, सहमति, जिम्मेदारी और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का महत्व समझाना होगा।

आज के समय में बच्चों और किशोरों पर उनके मित्रों, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। गलत संगत कई बार सही और गलत के बीच का अंतर कमजोर कर देती है। इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि परिवार ने संस्कार दिए हैं। परिवार, विद्यालय और समाज तीनों को मिलकर बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभानी होगी। युवाओं को यह समझाना होगा कि क्षणिक आवेश में लिया गया गलत निर्णय पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।

अपराध के बाद पीड़िता की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समाज को समझना होगा। किसी अपराध की सबसे बड़ी त्रासदी केवल घटना तक सीमित नहीं रहती। पीड़ित व्यक्ति को लंबे समय तक मानसिक पीड़ा, भय, सामाजिक दबाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी घटनाओं में पीड़िता को दोष देने, उसके चरित्र पर सवाल उठाने या घटना के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की मानसिकता पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। अपराध की जिम्मेदारी केवल अपराध करने वाले की होती है। परिवारों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे यदि किसी परेशानी में हों तो वे बिना डर अपनी बात परिवार के सामने रख सकें। घर ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बच्चा संकट में सबसे पहले अपने माता-पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता मांग सके। संवाद की कमी कई समस्याओं को गंभीर बना देती है। बच्चों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि परेशानी में घर लौटना शर्म की बात नहीं, बल्कि समझदारी है।

इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में त्वरित जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संरक्षण और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है। अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तेज और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत करती है। केवल कठोर सजा की घोषणा से अपराध नहीं रुकते; अपराध की निश्चित जांच, गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया का प्रभावी होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

चौदह वर्ष पहले दिल्ली में हुई निर्भया घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उसके बाद कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में गंभीर चर्चा हुई। फिर भी समय-समय पर सामने आने वाली घटनाएं बताती हैं कि कानून के साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन की जरूरत अभी समाप्त नहीं हुई है। किसी घटना के बाद कुछ दिनों तक आक्रोश व्यक्त करना पर्याप्त नहीं। वास्तविक बदलाव तब होगा जब महिलाओं का सम्मान हमारे व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा बनेगा।

यह भी याद रखना होगा कि हर अपराधी को केवल किसी दूसरे घर की बेटी के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। हर लड़की किसी की बेटी, बहन या परिवार का हिस्सा है, लेकिन उससे भी पहले वह स्वयं एक स्वतंत्र और सम्मानित इंसान है। महिलाओं का सम्मान रिश्ते के आधार पर नहीं, मानव गरिमा के आधार पर होना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को केवल सफल बनने की शिक्षा न दें, बल्कि अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी दें। पढ़ाई, नौकरी और आर्थिक सफलता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चरित्र, संयम और संवेदनशीलता के बिना ये उपलब्धियां अधूरी हैं। परिवारों में संवाद बढ़े, विद्यालयों में नैतिक एवं नागरिक शिक्षा को महत्व मिले, युवाओं को जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रेरित किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। दिल्ली की यह घटना पूरे समाज के लिए चेतावनी है। बेटियों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है और न ही केवल सरकार की। यह परिवार, विद्यालय, परिवहन व्यवस्था, प्रशासन और समाज–सभी की साझा जिम्मेदारी है। कठोर कानून अपराध के बाद न्याय दिला सकता है, लेकिन संस्कार और जागरूकता अपराध होने से पहले रोकने की शक्ति रखते हैं।

अंततः हमें यह संकल्प लेना होगा कि किसी भी महिला या बच्ची के सम्मान से खिलवाड़ को कभी सामान्य नहीं माना जाएगा। गलत को गलत कहने का साहस परिवार से लेकर समाज तक विकसित करना होगा। क्योंकि कानून का भय अपराधी को रोक सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार व्यक्ति को अपराध करने की सोच तक पहुंचने से रोकते हैं। जब कानून की मजबूती और संस्कारों की शक्ति साथ आएगी, तभी ऐसा समाज बनाया जा सकेगा जिसमें बेटियां भय के साथ नहीं, विश्वास और सम्मान के साथ घर से बाहर निकल सकें।

सोन के पानी पर समझौता, अब असली परीक्षा

सोन का पानी अब केवल नदी का सवाल नहीं है। बिहार और झारखंड के बीच करीब 25 साल से चला आ रहा जल विवाद समझौते की मेज तक पहुंचा है। नई दिल्ली में दोनों राज्यों ने सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौता किया है। हिस्सेदारी तय हो गई, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है–क्या यह पानी खेतों और घरों तक पहुंचेगा? क्या दोनों राज्य नदी को केवल बंटवारे की वस्तु मानने के बजाय साझा प्राकृतिक संसाधन की तरह देख पाएंगे? इस समझौते की सफलता इन्हीं सवालों के जवाब पर निर्भर करेगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल तथा दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्र ने इसे 'टीम भारत' की भावना और सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया है। लंबे समय से अटके किसी अंतरराज्यीय जल विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निस्संदेह महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी समझौते का महत्व उसके दस्तावेज में नहीं, उसके परिणाम में होता है।

सोन जल विवाद की पृष्ठभूमि 1973 के बाणसागर समझौते तक जाती है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड के गठन के बाद अविभाजित बिहार के हिस्से में रहे सोन के पानी के पुनर्वितरण का प्रश्न सामने आया। दोनों राज्यों के बीच यह मामला वर्षों तक उलझा रहा। अब बनी व्यवस्था के अनुसार बिहार को 5.75 मिलियन एकड़-फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़-फीट पानी का हिस्सा निर्धारित किया गया है।

यह हिस्सा दोनों राज्यों के ग्रामीण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना के बड़े इलाके सोन की सिंचाई व्यवस्था से जुड़े हैं। झारखंड में पलामू और गढ़वा सहित आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की जरूरत लंबे समय से बनी हुई है। ऐसे में जल की हिस्सेदारी का स्पष्ट निर्धारण दोनों राज्यों के लिए राहत का आधार बन सकता है।

बिहार में सोन की सिंचाई व्यवस्था ने कृषि को अपेक्षाकृत स्थिर आधार दिया है। वर्षा की अनिश्चितता बढ़ने के साथ इसकी उपयोगिता और बढ़ी है। समय पर सिंचाई मिले तो किसान एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय फसल विविधीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। उत्पादन और ग्रामीण आय में भी सुधार की संभावना है। झारखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इसका महत्व और व्यापक है, जहां सिंचाई के साथ पेयजल भी बड़ी समस्या है।

लेकिन यहीं समझौते की पहली और सबसे कठिन परीक्षा है। पानी का हिस्सा तय हो जाना और पानी का खेत तक पहुंचना अलग-अलग बातें हैं। नहरों की क्षमता, उनकी मरम्मत, जलाशयों का संचालन, वितरण नेटवर्क, बिजली और स्थानीय सिंचाई व्यवस्था तय करेगी कि समझौते का लाभ वास्तव में किसे मिलता है। देश में अनेक सिंचाई परियोजनाओं का अनुभव रहा है कि स्रोत पर पानी मौजूद रहने के बावजूद कमजोर वितरण व्यवस्था के कारण उसका पूरा लाभ अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता।

इसलिए समझौते के साथ स्पष्ट क्रियान्वयन योजना जरूरी है। दोनों राज्यों के बीच संयुक्त निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। जल प्रवाह, उपलब्धता और उपयोग के आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। किस मौसम में कितना पानी उपलब्ध है, कितना इस्तेमाल हुआ और किन क्षेत्रों को कितना पानी मिला–इनका नियमित हिसाब होना चाहिए। आधुनिक तकनीक से इसकी निगरानी संभव है। पारदर्शी आंकड़े राज्यों के बीच भरोसा बढ़ाने के साथ भविष्य के विवादों को भी रोक सकते हैं।

कम वर्षा या कम प्रवाह वाले वर्षों के लिए व्यवस्था और महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में हिस्सेदारी लागू करना आसान हो सकता है, लेकिन जल संकट के समय ही किसी समझौते की मजबूती सामने आती है। ऐसे समय में पेयजल, सिंचाई और नदी के पर्यावरणीय प्रवाह के बीच प्राथमिकता कैसे तय होगी, यह पहले से स्पष्ट होना चाहिए। संकट के समय यदि नियम अस्पष्ट रहे तो पुराना विवाद नए रूप में लौट सकता है।

अमित शाह ने सोन समझौते को सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया है। इस वर्ष अंतरराज्यीय जल और उससे जुड़े कई मामलों में केंद्र की मध्यस्थता से सहमति बनी है। नर्मदा परियोजना से जुड़े राज्यों के बीच लंबित भुगतान का निपटारा, राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर समझौता तथा किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना से जुड़े छह राज्यों के बीच सहमति इसी क्रम में हुई है।

इन घटनाओं को केवल समझौतों की संख्या के रूप में देखने के बजाय संघीय राजनीति में बदलती कार्यशैली के संकेत के रूप में देखना चाहिए। जल विवादों को लंबे समय तक राजनीतिक टकराव और कानूनी प्रक्रिया में उलझाए रखने के बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश सकारात्मक है। लेकिन सहकारी संघवाद का अर्थ केवल केंद्र की मध्यस्थता नहीं है। उसमें राज्यों के बीच बराबरी का भरोसा, पारदर्शिता और साझा जिम्मेदारी भी जरूरी है।

सोन के पानी का सवाल स्थानीय लोगों की भागीदारी से भी जुड़ा है। पानी के बारे में फैसले राजधानी में होते हैं, लेकिन उसका असर गांवों में दिखाई देता है। किसान, खेतिहर मजदूर, मछुआरे और नदी किनारे रहने वाले समुदाय नदी की बदलती स्थिति को सबसे पहले महसूस करते हैं। इसलिए जल प्रबंधन की व्यवस्था में स्थानीय अनुभव और जरूरतों को शामिल किया जाना चाहिए।

सोन को केवल सिंचाई की नहर में बदल देना भी दूरदर्शी नीति नहीं होगी। नदी का अपना पारिस्थितिक जीवन है। उसका प्राकृतिक प्रवाह भूजल पुनर्भरण, मिट्टी की नमी, जैव विविधता और नदी पर निर्भर आजीविका से जुड़ा है। यदि नदी से पानी निकालने की मात्रा बढ़ती रही और प्राकृतिक प्रवाह की चिंता नहीं की गई तो भविष्य में जल उपलब्धता का संकट और गहरा सकता है। जल बंटवारे में पर्यावरणीय प्रवाह को भी एक आवश्यक तत्व मानना होगा।

जलवायु परिवर्तन इस चुनौती को और गंभीर बना रहा है। बारिश का समय और वितरण पहले की तरह निश्चित नहीं रहा। कभी कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है, तो कभी लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इसलिए भविष्य की जल नीति को पुराने औसत आंकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता। नदी के प्रवाह और जल उपलब्धता का लगातार वैज्ञानिक आकलन आवश्यक है।

जल प्रबंधन का अर्थ केवल नदी से अधिक पानी लेना भी नहीं है। वर्षाजल संचयन, भूजल पुनर्भरण, स्थानीय तालाबों और जल संरचनाओं का संरक्षण तथा सूक्ष्म सिंचाई जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। खेत में पानी की दक्षता बढ़ेगी तो नदी पर दबाव कम होगा। फसल चयन को भी स्थानीय जल उपलब्धता के अनुरूप करने की जरूरत है। इस समझौते का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि सोन के पानी को विवाद की वस्तु से साझा विकास के संसाधन में बदला जा सकता है। बिहार और झारखंड की ऐतिहासिक निकटता इस सहयोग को आधार देती है। दोनों राज्यों की जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए पानी दोनों की समान आवश्यकता है।

इसलिए सोन समझौते को किसी एक राज्य की जीत या दूसरे की हार के रूप में देखना गलत होगा। पानी की साझेदारी का अर्थ है अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी साझा करना। बिहार को अपने हिस्से के पानी का उपयोग करते हुए झारखंड की जरूरत को समझना होगा और झारखंड को भी साझा नदी तंत्र की सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। इसी संतुलन से समझौता टिकाऊ बनेगा।

समझौते के बाद दोनों राज्यों को एक समयबद्ध कार्ययोजना बनानी चाहिए। नहरों और वितरण तंत्र की स्थिति का आकलन, आवश्यक निवेश, जल उपयोग की निगरानी और नियमित समीक्षा इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, विवाद खत्म होने के बाद संवाद खत्म नहीं होना चाहिए। नदी का स्वभाव बदलता है, इसलिए जल प्रबंधन की संस्थाओं को भी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप काम करना होगा।

सोन का अनुभव देश के दूसरे अंतरराज्यीय जल विवादों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पानी पर संघर्ष बढ़ने के पीछे केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि आंकड़ों की अस्पष्टता, अविश्वास और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। यदि राज्यों के बीच जल संबंधी आंकड़ों की साझेदारी, वैज्ञानिक आकलन और नियमित संवाद की व्यवस्था हो तो अनेक विवादों को गंभीर होने से पहले ही रोका जा सकता है।

इस पूरे मामले में एक बुनियादी सवाल फिर भी बना रहेगा–हम नदी को देखते कैसे हैं? यदि नदी को केवल बांध, नहर और जल की मात्रा के रूप में देखा जाएगा तो कोई भी समझौता अधूरा रहेगा। नदी एक जीवित प्राकृतिक तंत्र है, जिसके साथ मनुष्य की खेती, आजीविका और संस्कृति जुड़ी है। जल नीति को इस व्यापक दृष्टि की जरूरत है।

सोन पर हुआ समझौता इसलिए एक अंत नहीं, बल्कि शुरूआत है। करीब ढाई दशक पुराने विवाद को सुलझाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई गई है। अब उसी इच्छाशक्ति को प्रशासनिक दक्षता, वैज्ञानिक प्रबंधन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी में बदलना होगा।

अंततः इसकी सफलता का पैमाना कागज पर दर्ज 5.75 या 2 मिलियन एकड़-फीट पानी नहीं होगा। पैमाना यह होगा कि कितने खेतों तक सिंचाई पहुंची, कितने गांवों की पेयजल समस्या कम हुई और सोन का प्राकृतिक प्रवाह कितना सुरक्षित रहा।

सोन के पानी पर समझौता हो गया है। अब असली परीक्षा है–क्या पानी के साथ भरोसा भी बंटेगा, क्या विकास के साथ नदी भी बचेगी और क्या सहकारी संघवाद कागज से निकलकर खेत और गांव तक पहुंचेगा। यदि ऐसा हुआ तो यह समझौता केवल 25 साल पुराने विवाद का अंत नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय जल सहयोग की एक नई शुरूआत होगा।

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ज़नपद स्तरीय कला उत्सव का भव्य आयोजन

अमरोहा (सब का सपना):- राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अमरोहा के प्रांगण में आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासन के अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कला उत्सव का जनपद स्तरीय आयोजन उत्साह एवं गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य स्नेह लता की गरिमामयी उपस्थिति में माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कला उत्सव के अंतर्गत विभिन्न कला एवं सांस्कृतिक विधाओं का समायोजन किया गया। इनमें नृत्य, गायन, वादन, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थानीय खेल एवं खिलौने तथा पारंपरिक कहानी वाचन सहित कुल 12 विधाओं में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक विरासत की सुंदर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम का सफल एवं आकर्षक मंच संचालन बीना रानी, कीर्ति एवं मीना देवी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी शिक्षिका ममता यादव एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गठित निर्णायक मंडल में कीर्ति, ममता दलेला, पूनम मैथ्यू, अनुराधा, आयुषी, शिखा, शैली राजपूत, इलमास, अखिलेश चौधरी, आलोक यादव, आलोक पाठक एवं आसिम अब्बासी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को अपनी कला एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ भारतीय लोक संस्कृति, परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। संपूर्ण कार्यक्रम उल्लास, सृजनात्मकता एवं सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण रहा।

आईटीआई में प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश 04 सितम्बर तक

अमरोहा (सब का सपना):- राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ द्वारा जनपद के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण सत्र 2026 हेतु प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 04 सितम्बर 2026 सायं 05:00 बजे निर्धारित की गई है। प्रथम चरण में चयनित सभी अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्थान में निर्धारित समय प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक उपस्थित होकर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र, स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, चार नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक अभिलेखों के साथ चयन सूची के अनुसार सत्यापन कराते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। अवकाश के दिनों में भी प्रवेश प्रक्रिया यथावत संचालित रहेगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 04 सितम्बर 2026, सायं 05:00 बजे है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रवेश का अवसर उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थी समय से प्रवेश सुनिश्चित करें। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हसनपुर वर्तमान में ग्राम रहरई, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा स्थित परिसर में संचालित है। जनपद के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहसपुर जौया के समस्त चयनित अभ्यर्थी प्रवेश हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अमरोहा (ग्राम केशोपुर, कैलसा रोड, अमरोहा) में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

अमरोहा में तेंदुए की समस्या, मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के उपाय

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद में गन्ने की फसल का सीजन चल रहा है और जगह-जगह तेंदुए की दहशत फैल गई है। मानव-वन्यजीव संघर्ष के इस दौर में स्थानीय लोगों की सुरक्षा और जानवरों के संरक्षण दोनों जरूरी हो गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि शाम अंधेरा होने से पहले और सुबह सूर्योदय से पहले जंगल या घने खेतों में न जाएं। यह समय तेंदुए सहित जंगली जानवरों के शिकार का होता है। दिन में भी खेतों में काम करने के लिए अकेले न जाएं। समूह बनाकर शोर मचाते हुए जाएं, ताकि तेंदुए को मनुष्यों की उपस्थिति का एहसास हो। तेंदुआ आमतौर पर धोखे में हमला करता है। अगर उसे पता चले कि आसपास मनुष्य हैं तो वह हमला करने से बचता है।

वन विभाग ने सलाह दी है कि रात में घरों के आसपास रोशनी रखें, पालतू जानवरों को सुरक्षित बंद रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें। फसल क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाई जा रही है।

अमरोहा में मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक प्रयास ही सबसे प्रभावी समाधान हैं। नागरिकों से अपील है कि वन्य जीवों का सम्मान करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि दोनों पक्ष सुरक्षित रह सकें।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट, अमरोहा में होगा सजीव प्रसारण

अमरोहा (सब का सपना):- शासन के निदेशों के क्रम में 02 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे लोक भवन स्थित प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम का जनपद स्तर पर आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम में सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के बढ़े हुए पारिश्रमिक की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विभागों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्सिंग एवं सफाई कार्मिकों उपस्थिति रहेंगे। श्रम विभाग द्वारा BOCW लाभार्थियों के चयन/सूची तैयार करने तथा चेक वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही आउटसोर्सिंग कार्मिकों को EPF/ESIC आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सेवायोजन विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता, सेवा संबंधी अवसर एवं रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सामग्री एवं प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

धनौरा ब्लॉक परिसर में प्रधान संघ की बैठक का आयोजन, विकास कार्यों पर हुई चर्चा, स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने की मांग

धनौरा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद की मंडी धनौरा ब्लॉक परिसर में मंगलवार को प्रधान संघ की एक बैठक का आयोजन कराया गया। इस बैठक के दौरान प्रधान संघ के सदस्यों ने विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर विशेष चर्चा की साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की, जिसको लेकर प्रधान संघ के सदस्यों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ब्लॉक अध्यक्ष उधम गिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई।बैठक में बताया गया कि राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की निधि से बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इससे हैंडपंप मरम्मत, रीबोर, नाली-नाला सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग और सीसी रोड जैसे कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। बैठक के बाद प्रशासकों ने बीडीओ प्रतिभा अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने की मांग की।बैठक में ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित विकास कार्यों और जनसुविधाओं से संबंधित कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। प्रशासकों ने बताया कि कई कार्य स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में हैं।बैठक में हैंडपंप मरम्मत, रीबोर, नाली-नाला सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग सड़क और सीसी रोड निर्माण जैसे कार्यों को जल्द शुरू कराने की आवश्यकता बताई गई।बैठक के बाद सभी प्रशासकों ने खंड विकास अधिकारी प्रतिभा अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें विकास खंड की ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित जनहित के कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने और निर्माण एवं मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की गई।प्रधान संघ धनौरा ब्लॉक अध्यक्ष उधम गिल ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को समय से पूरा कराने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी जरूरी है। उन्होंने संबंधित कार्यों को जल्द शुरू कराने की मांग रखी।

बैठक में उधमगिल, विक्रम सिंह, चीनू जाटव, पुष्पेंद्र सिंह, राजपाल जाटव, गंगासरन सिंह, लाल सिंह, परमपाल सिंह, जितेंद्र कुमार, हरीश यादव, फाजिल जैदी, विनोद कुमार, कविंदर सिंह, जितेंद्र और रिफाकत अली समेत क्षेत्र के कई ग्राम प्रशासक मौजूद रहे।

भाकियू (शंकर) ने किसान संबंधी समस्याओं को लेकर अपर जिलाधिकारी न्यायिक को सौंपा मांग-पत्र

अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के किसानों एवं आमजन की विभिन्न गंभीर समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), अमरोहा से वार्ता कर मांग-पत्र सौंपा। बता दें कि मांग-पत्र के माध्यम से जनपद की किसानहित एवं जनहित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इनमें जिला सहकारी बैंक लिमिटेड अमरोहा का गठन, KCC की सीमा 5 लाख करने एवं ब्याज दर पुनः 3 प्रतिशत करने, किसानों से वसूले गए अतिरिक्त ब्याज की वापसी, अमरोहा विकास प्राधिकरण की स्थापना, मध्य गंगा नहर फेस-2 एवं बहजोई ब्रांच में पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने, डिडौली में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, गजरौला ट्रॉमा सेंटर का संचालन, हसनपुर चीनी मिल से जुड़े लंबित कार्य एवं किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान प्रमुख रूप से शामिल रहे।इसके अलावा ब्रजघाट से मुरादाबाद मार्ग पर अनावश्यक स्पीड ब्रेकरों की समस्या, राष्ट्रीय राजमार्ग-9 एवं सर्विस लेनों पर जलभराव, गजरौला चौपला पर यातायात जाम,रजबपुर-काफूरपुर-चांदनगर-धकतौड़ा-गुलड़िया मार्ग सहित जनपद की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण, ई-रिक्शा के व्यवस्थित संचालन, तिगरी धाम के विकास एवं विद्युत शवदाह गृह की स्थापना जैसी समस्याओं को भी मांग-पत्र में प्रमुखता से रखा गया।वहीं जनपद में गोवंशीय पशुओं में फैल रहे लंपी रोग की रोकथाम के लिए प्रत्येक गांव में विशेष टीम गठित कर जांच एवं टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की गई। साथ ही तेंदुआ, बंदर, आवारा कुत्तों एवं आवारा गोवंश की समस्या के स्थायी समाधान की भी मांग उठाई गई।वार्ता के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने किसान प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान संभव है, उनके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा तथा जो समस्याएं नीतिगत स्तर की हैं,उन्हें शासन को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा।राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि किसान और आमजन की समस्याओं को लेकर संगठन लगातार संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि मांगों पर केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस एवं समयबद्ध कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए।

संगठन शासन एवं प्रशासन से सकारात्मक एवं प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करता है।इस अवसर पर चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी नेमपाल सिंह, मोनू चौधरी, चौधरी विक्रम पवार, चंद्रभान सैनी, रमेश्वर सैनी, तेजपाल सैनी, अख्तव, सत्यवीर सिंह, सत्येंद्र सिंह,मा जगत सिंह राकेश सहित भारतीय किसान यूनियन (शंकर) के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

थाना रजबपुर में सड़क हादसे में घायल हुई महिला ने कार चालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज

रजबपुर/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के थाना रजबपुर में सड़क हादसे में घायल हुई एक महिला ने कार चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि यह पूरी घटना 2 अगस्त 2026 की शाम करीब आठ बजे हुई। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव शकरपुर समसपुर निवासी शबाना मलिक, जो इसरत अली की पत्नी हैं, गजरौला से नौकरी कर बाइक से अपने घर लौट रही थीं। होटल नीलकंठ स्टार के पास पहुंचते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर लगने से शबाना सड़क पर गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। तहरीर के अनुसार, उनके पैर और हाथ में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं, साथ ही दोनों कमर और शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां भी टूट गई हैं। टक्कर मारने वाली कार का नंबर UP14 EB 1400 बताया गया है।शबाना जिस बाइक पर सवार थीं, उसका नंबर UP23 AE 9775 है। पीड़ित पति इसरत अली ने रजबपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने 31 अगस्त को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रजबपुर थाना प्रभारी विकास कुमार सहरावत ने बताया कि प्रकरण में जांच और वैधानिक कार्यवाही जारी है।

नौगांवा सुधांशु हत्याकांड मामले में बुलडोजर कार्यवाही की मांग को लेकर पिता पानी की टंकी पर चढ़ा

नौगांवा/अमरोहा (सब का सपना):- जनपद के नौगांवा सादात क्षेत्र में हुए सुधांशु हत्याकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही की मांग को लेकर मृतक का पिता निर्माणधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर तुरंत भारी पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। जिन्होंने पानी की टंकी पर चढ़े मृतक युवक के पिता को सकुशल नीचे उतरने का प्रयास किया। बता दें कि जनपद के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गुलड़िया गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति अपने बेटे के हत्यारोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर निमार्णाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया।पीड़ित कृतिपाल नामक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से करीब एक घंटे पहले से टंकी पर चढ़ा हुआ था।सूचना मिलते ही एसडीएम सदर शशि भूषण पाठक और नौगावां सादात क्षेत्राधिकारी अवधभान सिंह भदौरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से बातचीत कर उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया।यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। दरअसल इस मामले में जानकारी के मुताबिक बीती 9 अगस्त को गांव निवासी अरविंद ने 21 वर्षीय सुधांशु प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, दोनों के बीच ब्याज के पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था।सुधांशु की हत्या के बाद से ही उसके परिजन लगातार आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और इससे पहले भी पीड़ित परिवार ने समाज के तमाम लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी और बुलडोजर चलाने की मांग की थी।पुलिस ने घटना के अगले दिन ही मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, परिजनों ने पोस्टमार्टम वाले दिन भी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीएम हाउस पर जमकर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी थी।

अमरोहा में मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ने का यह दूसरा मामला सामने आया है। इससे दो दिन पहले धनौरा थाना क्षेत्र के कैसरा गांव में एक विधवा महिला भी अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिलहाल, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं और मृतक के पिता को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास लगातार जारी हैं।

भारत को जानो प्रतियोगिता में 52 विद्यार्थियों ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा

बहजोई/संभल (सब का सपना):- भारत विकास परिषद बहजोई मंगलम शाखा के तत्वावधान में बीएमबीएल जैन वर्ल्ड स्कूल में भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा छह से आठ तक के 52 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर भारतीय इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार जैन ने कहा कि भारत को जानो जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, महापुरुषों और राष्ट्रीय विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसी गतिविधियों से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि के साथ उनमें राष्ट्र के प्रति गौरव और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ ज्ञानवर्धक और संस्कारपरक कार्यक्रम भी जरूरी हैं। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता से अधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेना और निरंतर सीखते रहना है। भारत विकास परिषद के प्रांतीय वित्त सचिव राहुल वार्ष्णेय एडवोकेट ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को जानना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रबोध के प्रति रुचि बढ़ती है। कार्यक्रम में लव कुमार आर्य, चेयरमैन डॉ. पवन कुमार जैन, निदेशक सम्भव जैन, प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता, उप प्रधानाचार्य गौरव मेधावर्त, मेधावी आर्य, नव्या गुप्ता, शैवाली वार्ष्णेय, रुचि गुप्ता, राधा नेगी सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनमें राष्ट्रबोध की भावना विकसित करना रहा।

अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण का हुआ समापन, मूल्यांकन में परखी प्रशिक्षणार्थियों की दक्षता

ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर दिया जा रहा जोर

बहजोई/संभल(सब का सपना):- केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), बहजोई के तत्वावधान में असमोली में संचालित अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण बैच का मंगलवार को अंतिम मूल्यांकन के बाद सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संभल जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को अगरबत्ती निर्माण से जुड़ी तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया। प्रशिक्षणार्थियों का अंतिम मूल्यांकन ईडीपी असेसर राजीव कुमार (चंदौसी) एवं डोमेन असेसर आरती (अमरोहा) ने किया। मूल्यांकन के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा, प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान, अगरबत्ती निर्माण की व्यावहारिक जानकारी, कार्यकुशलता तथा मौखिक प्रश्नों के माध्यम से दक्षता परखी गई। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों ने मूल्यांकनकताओं के साथ स्मृति स्वरूप ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। समापन अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई दिया। संस्थान की ओर से बताया गया कि अगरबत्ती निर्माण जैसे रोजगारपरक प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं महिलाओं को आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी अपना स्वरोजगार शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर मानसी शर्मा, सुजीत सिंह, विशेष, रनवीर सिंह सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। वर्तमान में संस्थान में डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स के माध्यम से 30 युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान निदेशक अनुपम कुमार गुप्ता ने बताया कि आगामी समय में महिला सिलाई, मत्स्य पालन, मोबाइल रिपेयरिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग, राजमिस्त्री सहित विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मंगलवार से मोबाइल रिपेयरिंग, एसी एवं फ्रिज रिपेयरिंग, उद्यमिता विकास और सिलाई आदि प्रशिक्षण बैचों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक युवा केनरा बैंक आरसेटी, बहजोई के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिए 05921-297253 एवं 7906846414 पर संपर्क किया जा सकता है।

दस सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू ने ब्लॉक परिसर में दिया धरना

गन्ने का रेट 600 प्रति क्विंटल करने समेत सड़क, राशन, आवास और रेल विस्तारीकरण की उठाई मांग

संभल(सब का सपना):- भारतीय किसान यूनियन (बीआरएसएस) भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की ओर से मंगलवार को विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ब्लॉक संभल परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने किया, जबकि अध्यक्षता चौ. ऋषिपाल सिंह तथा संचालन निर्देश कुमार ने किया। इस दौरान संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगपत्र उपजिलाधिकारी विकास चन्द्र के माध्यम से सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सम्भल कामेन्द्र चौधरी ने कहा कि संगठन लंबे समय से आमजन और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग कर रहा है, लेकिन कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने गांवों की टूटी सड़कों की मरम्मत, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, पात्र लोगों को आवास एवं राशन कार्ड का लाभ देने तथा बिजली के बढ़े हुए बिलों की समस्या दूर करने की मांग उठाई। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने कहा कि गन्ने का रेट 600 प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। खाद, बीज, डीजल, बिजली और मजदूरी महंगी होने के कारण खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना जरूरी है। धरने के दौरान मनरेगा में पारदर्शिता, पेयजल आपूर्ति, हर घर जल योजना की जांच, सम्भल में शीघ्र रेल विस्तारीकरण, गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर गांवों के नाम के साइन बोर्ड लगवाने तथा ग्राम चमरौआ के उच्च प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का निर्माण कराने की मांग भी उठाई गई। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की गई। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि भाकियू किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान धरातल पर होना चाहिए और अधिकारियों को गांवों में पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिए। मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने में उपजिलाधिकारी सम्भल विकास चन्द्र, खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह, समाज कल्याण विभाग से विनीता सैनी, सहायक विकास अधिकारी अमित यादव, विद्युत विभाग के एसडीओ चन्द्रभूषण सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष अरोड़ा, आपूर्ति निरीक्षक अंकित अवस्थी, असमोली से ललित कुमार, पंवासा से तारावती, जल मिशन जेई धर्मवीर गौतम, यूपीडा इंजीनियर प्रदीप कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना समाप्त किया गया।

इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री चौ. ऋषिपाल सिंह, जिला महासचिव अनमोल कुमार, जिला प्रचार मंत्री सन्तवीर सिंह, जिला महामंत्री इस्माइल खां, जिला मंत्री खेमपाल यादव, सुफियान पाशा, युवा जिला मीडिया प्रभारी निर्देश कुमार, तहसील अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह, सेवक सैनी, श्रीपाल यादव, राजीव कुमार, मनीराम गुर्जर, नरेन्द्र चौधरी, सतीश कुमार, मो. हसन सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जलभराव की समस्या को लेकर व्यापारियों ने उठाई आवाज जल्द स्थायी समाधान का मिला आश्वासन

सम्भल(सब का सपना):- नगर में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान 74/22 के पदाधिकारियों ने नगर में जगह-जगह हो रहे जलभराव के कारण व्यापारियों और आमजन को हो रही परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों के व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने नगर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराने तथा जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग रखी। व्यापारियों की समस्याएं सुनने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल्द आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। व्यापारियों ने प्रशासन से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनंत अग्रवाल, महामंत्री शोभित गुप्ता, युवा जिला अध्यक्ष अरविन्द कुमार प्रजापति, नगर अध्यक्ष नवील अहमद, जिला उपाध्यक्ष जमीलुर्रहमान, मुजीबउररहमान सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने प्रशासन को नगर की समस्याओं से लगातार अवगत कराने और उनके समाधान में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

बिजली के तार चोरी की झूठी कहानी का पुलिस ने किया खुलासा

गोदाम मालिक के कर्मचारी समेत सात गिरफ्तार, चोरी का करीब 30 कुंतल तार और वाहन बरामद

बहजोई/संभल(सब का सपना):- जनपद के थाना कैलादेवी पुलिस ने बिजली के तार चोरी के मामले का खुलासा करते हुए वादी समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने करीब 30 कुंतल बिजली के तार चोरी होने की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के बिजली के तार सहित छोटा हाथी और घटना में प्रयुक्त वैगनार कार बरामद की है। पुलिस के मुताबिक 28 अगस्त को आनन्द शुक्ला पुत्र मुन्ना शुक्ला निवासी ग्राम शनिपुर, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर ने थाना कैलादेवी में तहरीर देकर बताया था कि रात में चार अज्ञात बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और टीन शेड व कमरे में रखे बिजली के तारों के चार ड्रम काटकर छोटे हाथी में भरकर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीमों का गठन कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से छोटा हाथी और वैगनार कार की पहचान हुई। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम भटौला के पास अंडरपास, गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे दबिश देकर छह आरोपियों को छोटा हाथी में चोरी के बिजली के तार तथा घटना में प्रयुक्त वैगनार कार के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ और जांच में सात आरोपियों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें अली खान, समशुल, खुशनूद अली, गौतम सिंह, पुष्पेन्द्र, अरशद और आनन्द शुक्ला शामिल हैं। पूछताछ में आनन्द शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने गौतम के मोबाइल पर बिजली के तार बेचने के संबंध में बात की थी। इसके बाद सम्भल निवासी शेरे पठान गोदाम पर माल देखने आया था। उसने दिल्ली की पार्टी से बातचीत कर तार उठवाने की बात कही थी। पुलिस के अनुसार 27 अगस्त की रात दिल्ली की पार्टी के लोग वाहन लेकर पहुंचे, जिसके बाद गोदाम से दो ड्रम नए बिजली के तार और दो ड्रम पुराने तार करीब 30 कुंतल माल वाहनों में लादकर भेज दिया गया। इसके बदले दो लाख रुपये मिलने थे, लेकिन रुपये नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आनन्द शुक्ला ने अपने मालिक संजय श्रीवास्तव को गुमराह करते हुए चार बदमाशों द्वारा पकड़कर तार चोरी किए जाने की झूठी कहानी बताई और थाने में भी उसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। जांच में यह भी सामने आया कि घटना से चार दिन पहले आनन्द शुक्ला ने अपने गोदाम से कबाड़ी अरशद को दो कुंतल बिजली का तार 27 हजार रुपये में बेचा था। पुलिस ने बताया कि इसमें से 25 हजार रुपये आनन्द शुक्ला के कब्जे से बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार घटना में अन्य वाहन और कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा रिमांड के लिए भेजा जा रहा है।

लंबे समय से अटकी मजदूरी का हुआ भुगतान, श्रमिकों ने जताया आभार

सम्भल(सब का सपना):- लंबित मजदूरी के भुगतान को लेकर प्राप्त शिकायतों पर श्रम विभाग ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत प्रकरणों की सुनवाई की। सहायक श्रम आयुक्त रामलखन पटेल ने सेवायोजक पक्ष से वार्ता कर श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान कराया। पहले प्रकरण में श्रमिक ममता एवं अन्य की शिकायत पर सहायक श्रम आयुक्त ने सेवायोजक पक्ष प्रगमैटिक इन्फ्रा प्रा. लि. के स्वामी/प्रतिनिधि से वार्ता कराई। दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद ममता, बृजभूषण, हरदयाल, मातादीन, महेश, रतीराम, अनिल, यथोदा, इन्द्रा, पूजा एवं तुलसा को कुल 82 हजार रुपये की बकाया मजदूरी का भुगतान कराया गया। इसके अलावा कार्यालय आने-जाने के किराये के रूप में श्रमिकों को 4,500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी कराया गया। वहीं दूसरे प्रकरण में शिकायतकर्ता हरनाम सिंह, धर्म सिंह आदि की शिकायत पर सेवायोजक पक्ष मै. अभिलाषा इंटरप्राइजेज से वार्ता के बाद श्रमिकों के बकाया वेतन 67,268 रुपये का भुगतान कराया गया। इस प्रकार दोनों मामलों में श्रमिकों को कुल 1,53,768 रुपये का भुगतान कराया गया। बकाया मजदूरी प्राप्त होने पर शिकायतकताओं ने सहायक श्रम आयुक्त रामलखन पटेल के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रम विभाग के वाद लिपिक ललित कुमार ने बताया कि जनपद में किसी भी श्रमिक की मजदूरी सेवायोजक के यहां बकाया है और भुगतान लंबित है तो संबंधित श्रमिक कार्यालय/न्यायालय सहायक श्रम आयुक्त, सम्भल में उपस्थित होकर नियमानुसार वाद दायर कर सकते हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर श्रमिकों को उनकी बकाया मजदूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

राष्ट्रपति भवन में राखी बांधकर लौटे विद्यार्थियों का वैश्य एकता समिति ने किया सम्मान

चंदौसी/संभल(सब का सपना):- वैश्य एकता समिति, प्रान्त सम्भल की ओर से नगर के कैथल गेट चंदौसी स्थित न्यू सत्यम एकेडमी की प्रधान अध्यापिका नमिता चौधरी एवं छात्र-छात्राओं को राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राष्ट्रपति को राखी बांधने और कुशल भेंट करने का गौरव प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। समिति पदाधिकारियों ने प्रधान अध्यापिका एवं विद्यार्थियों को पटका पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष एडवोकेट लवित वार्ष्णेय ने कहा कि वैश्य समाज के विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति को राखी बांधकर चंदौसी नगर, विद्यालय एवं पूरे वैश्य समाज का मान-सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है। समिति की ओर से छात्र-छात्राओं रुहान्श, माधव गुप्ता, अक्षिता एवं पावनी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा और उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए संगठन आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

इस मौके पर समिति अध्यक्ष एडवोकेट लवित वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष दीपेश सेठ, महामंत्री आकाश वार्ष्णेय, हेमंत वार्ष्णेय, मयंक वार्ष्णेय, सीए पीयूष बंसल, विकास वार्ष्णेय, सचिन कुमार, राजा गुप्ता, मनीष गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बहजोई/सम्भल(सब का सपना):- कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देशन में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्यप्रिय सिंह ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, संतुष्ट एवं असंतुष्ट फीडबैक तथा आईजीआरएस पोर्टल और हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई।

अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली आख्या का गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण करने के बाद ही उसे अपलोड किया जाए। जिन शिकायतों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, उनका स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण समाधान कराया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए, जिससे शिकायतकर्ता असंतुष्ट होकर दोबारा शिकायत करने को मजबूर हो।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि आख्या में तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान किया जाए। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों की आख्या डिफॉल्टर होने से कम से कम दो दिन पहले पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, ताकि समय रहते उसका अध्ययन और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सभी अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में उप जिलाधिकारी सम्भल विकास चंद्र, संबंधित समस्त डिप्टी कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी राम आशीष, एआरटीओ अमिताभ चतुवेर्दी, उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, आईजीआरएस पटल सहायक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

अमरोहा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन

अमरोहा (सब का सपना):- पशुपालन विभाग की टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित खादर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पशु चिकित्सा अधिकारी आजमपुर डॉ. भागेश सिंह के नेतृत्व में हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक राजीव तरारा ने फीता काटकर और गौ पूजन कर किया। इस अवसर पर विधायक जी ने शिविर की सराहना करते हुए ग्रामवासियों से लाभ उठाने की अपील की तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिले की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आमादन्त ने पशुपालकों को बाढ़ के बाद होने वाले रोगों से बचाव के उपाय बताए तथा डॉ. भागेश सिंह को खादर क्षेत्र में ऐसे शिविर लगाने के निर्देश दिए। शिविर में कुल 67 पशुओं का उपचार किया गया तथा 70 पशुपालकों को मिनरल मिक्सर व डीवर्मिंग की गोलियां निशुल्क वितरित की गईं। शिविर का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ खादर क्षेत्र में पशुओं का निशुल्क उपचार करना था।

मंच का संचालन डॉ. भागेश सिंह ने किया। इस अवसर पर उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी धनौरा डॉ. दीपाक्षी, सुरेन्द्र कौन्दिर, धर्मपाल, जयप्रकाश, कृष्णा, आकाश, नौसिंह, महावीर सिंह, इद्रीश, सुरेश सिंह तथा ग्राम प्रधान रम्पुरा प्रेमपाल, मंगतराम, कृष्ण आदि का सराहनीय सहयोग रहा।

जंगली हाथियों ने रौंदी किसान की चार बीघा गन्ने की फसल

हाथियों के झुंड के खेत में घुसने से किसानों में दहशत, वन विभाग के प्रयासों के बावजूद नहीं थम रहा आतंक

बिजनौर (सब का सपना):- साहूवाला वन रेंज क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहा है। ग्राम इनायतपुर में जंगली हाथियों ने किसान योगेश कुमार की करीब चार बीघा गन्ने की फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया। फसल बर्बाद होने से किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बताया गया कि जंगली हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर अचानक किसानों के खेतों में दाखिल हो गया। हाथियों ने खेत में खड़ी गन्ने की फसल को रौंद डाला। किसान योगेश कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब 1500 रुपये प्रति कुंतल की दर से गन्ने का बीज खरीदकर खेत में फसल बोई थी। फसल तैयार होने से पहले ही हाथियों के झुंड ने उसे रौंदकर बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली हाथी आए दिन जंगल से निकलकर खेतों में पहुंच जाते हैं और गन्ने समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों में भय का माहौल बना हुआ है। किसानों का कहना है कि एक ओर खेती की लागत और महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर जंगली जानवरों के कारण फसलें बर्बाद होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि वन विभाग की टीम द्वारा जंगली हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली हाथियों को खेतों में आने से रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाने तथा फसल के नुकसान का उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।

कोटेदारों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, लाभांश में 35 रुपये की बढ़ोतरी

90 से बढ़कर 125 रुपये प्रति क्विंटल हुआ लाभांश – जिलेभर के उचित दर विक्रेताओं में खुशी, मुख्यमंत्री व खाद्य मंत्री का जताया आभार

बिजनौर (सब का सपना):- प्रदेश की योगी सरकार ने उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की घोषणा से जनपद बिजनौर के कोटेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार के इस निर्णय को लेकर उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद (पंजीकृत) के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार अहलावत के नेतृत्व में जिलेभर के कोटेदारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन भेजकर आभार व्यक्त किया।

कोटेदारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय

जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार अहलावत ने कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे गांव-गांव और शहरों में गरीब, जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों तक सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे में लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कोटेदारों के आर्थिक हितों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय कोटेदारों के लिए राहत और सम्मान दोनों लेकर आया है। वहीं खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कोटेदारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें शासन तक पहुंचाया, जिसके लिए परिषद उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करती है।

आगे भी सकारात्मक फैसलों की उम्मीद

परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से उचित दर विक्रेताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं खाद्य मंत्री के प्रति आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि भविष्य में भी कोटेदारों की लंबित समस्याओं के समाधान और उनके हितों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक निर्णय लिए जाते रहेंगे। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेता एवं परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे।

बेटा न होने पर प्रताड़ित करने के मामले में पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज

नगीना/बिजनौर सब का सपना):- बेटा न होने पर प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर पति सहित ससुराल पक्ष के छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अपनी कारवाही शुरू कर दी है। स्थानीय मौहल्ला कलालान निवासी शबनम पत्नी शाफेज ने दी गई तकरीर में कहा है कि उसका निकाह नौ वर्ष पूर्व मोहल्ले के ही शाफेज पुत्र हसीनुद्दीन के साथ हुआ था।जिससे उसे दो बेटियां पैदा हुई। पीड़िता शबनम का आरोप है कि बेटा पैदा न होने के कारण पति शाफेज, सास रशीदा, ससुर हसीनुद्दीन,नन्द सोनी व नरगिस तथा देवर अजीम गाली गलौच व मारपीट करते हैं और दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं।पीड़िता शबनम ने यह भी आरोप लगाया है कि पति शाफेज शराब पी कर मारपीट करता है और कहता है कि तू लड़का पैदा कर अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा।पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (विवाहिता के साथ क्रूरता करने, 115(2)चोट पहुंचाने, 352 अपमानित करने व 351(2)धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपनी कारवाही शुरू कर दी है।

थाने से चंद कदम दूर मकान में चोरी का प्रयास, मचा हड़कंप

मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर, खिड़कियों की जालियां तोड़ीं; बल्ब व बिजली बोर्ड भी किए क्षतिग्रस्त

हीमपुर दीपा/बिजनौर (सब का सपना):- थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक मकान में चोरों ने चोरी का प्रयास कर सनसनी फैला दी। चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और दोनों कमरों की खिड़कियों की जालियां तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान घर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीमपुर दीपा बस स्टॉप के पास स्वर्गीय रामरतन का मकान है, जिसमें उनकी पत्नी सुधा देवी रहती हैं। बताया गया कि रक्षाबंधन के अवसर पर सुधा देवी अपने भाई को राखी बांधने चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव अकोंधा गई थीं। इसी दौरान रात में शातिर चोरों ने मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने सबसे पहले मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद दोनों कमरों की खिड़कियों की जालियों को घर में रखे वाइपर की मदद से क्षतिग्रस्त कर अंदर घुसने का प्रयास किया। चोरों ने घर में लगे जलते बल्ब और बिजली के बोर्ड को भी तोड़ दिया। खिड़कियों की जालियां क्षतिग्रस्त करने के साथ ही घर के अंदर अन्य सामान में भी तोड़फोड़ की गई। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर सुधा देवी अपने भाई के घर से वापस मकान पर पहुंचीं।

उन्होंने बताया कि घर से क्या-क्या सामान चोरी हुआ है, इसका आकलन करने के बाद पुलिस को सूचना दी जाएगी। थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से घटना का खुलासा कर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सूत मिल से मिट्टी खनन की शिकायत पर एसडीएम ने पकड़ीं चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां

मंडी समिति में खड़ी कराई गईं गाड़ियां, ठेकेदार ने कहा जमीन समतलीकरण का मिला है ठेका, अलग से मिट्टी खोदने का नहीं

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- कोतवाली मार्ग स्थित वर्षों से बंद पड़ी सहकारी कताई मिल से कथित रूप से मिट्टी खोदकर कॉलोनियों में भराव कराए जाने की शिकायत पर एसडीएम प्रिंस कुमार ने कार्रवाई करते हुए चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को हिरासत में लेकर मंडी समिति में खड़ा करा दिया। कार्रवाई से संबंधित लोगों में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगीना की सहकारी कताई मिल करीब 25-26 वर्षों से बंद पड़ी है। शासन की ओर से यहां संत कबीर टेक्सटाइल लगाए जाने की घोषणा के बाद कानपुर इंडस्ट्रियल विभाग के अधिकारियों द्वारा करीब दो-तीन माह पूर्व पेड़ों को छोड़कर मिल के भवन, मशीनरी, केबिल सहित अन्य सामग्री की नीलामी करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये में की गई थी। नीलामी बैंगलोर की फर्म कमल ट्रेडर्स के नाम हुई थी। बताया गया कि मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे एसडीएम प्रिंस कुमार को सूचना मिली कि मिल परिसर से अलग से मिट्टी खोदकर कथित रूप से अवैध खनन किया जा रहा है और मिट्टी को कॉलोनियों में भराव के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष जायसवाल, कानूनगो नरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार व लेखपाल सहित टीम के साथ मौके की ओर रवाना हुए। टीम ने मंडी समिति के पास से आ रही चार-पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोक लिया। इस दौरान एक चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली खाली कर मौके से भाग निकला, जबकि चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को हिरासत में लेकर मंडी समिति में खड़ा करा दिया गया। सूचना मिलने पर कमल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अमित वर्मा भी मंडी समिति पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को बताया कि उन्हें इंडस्ट्रियल विभाग कानपुर की ओर से पेड़ों को छोड़कर मिल की जमीन को समतल करने का ठेका मिला है। उनके अनुसार अलग से मिट्टी खोदने का कोई ठेका नहीं लिया गया है। भवनों को तोड़ने के दौरान निकलने वाले मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद एसडीएम ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मिल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवनों की तुड़ाई का कार्य तथा निकलने वाले मलबे को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरने का कार्य होता मिला। एसडीएम ने ठेकेदार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मिल परिसर से अलग से मिट्टी खोदकर खनन किए जाने की शिकायत मिलने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की आधिकारिक जानकारी लेने के लिए मीडिया कर्मी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसडीएम कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। काफी इंतजार के बाद मीडिया कर्मियों ने मोबाइल फोन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। एडीएम राजस्व से भी फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं, जिला खनन अधिकारी से फोन पर मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी होने से इनकार किया। ऐसे में मिल परिसर में चल रहे कार्य और मिट्टी के उठान को लेकर स्थिति पर प्रशासन की ओर से विस्तृत और स्पष्ट जानकारी सामने आना अभी बाकी है।

दूसरी बार बार अध्यक्ष बने दीपक बिश्नोई का समाज ने किया भव्य स्वागत

अधिवक्ताओं के हितों के साथ समाज के पीड़ित लोगों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का भरोसा

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- बिश्नोई मंदिर परिसर स्थित बिश्नोई सराय धर्मशाला में बिश्नोई समाज की ओर से बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक बिश्नोई का स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाज के लोगों ने उन्हें दूसरी बार बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए इसे पूरे समाज के लिए गौरव की बात बताया। प्रमुख ट्रांसपोर्टर रोहिताश बिश्नोई की अध्यक्षता तथा डॉ. बालेश बिश्नोई के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दीपक बिश्नोई पूर्व में भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब दूसरी बार अध्यक्ष बनने से बिश्नोई समाज का गौरव बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अधिवक्ताओं के हितों की पैरवी करने के साथ-साथ समाज के लोगों की समस्याओं एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। स्वागत से अभिभूत बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक बिश्नोई ने कहा कि समाज की ओर से मिले सम्मान और स्नेह के इन पलों को वह हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेंगे। उन्होंने कहा कि वह अधिवक्ताओं के हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने के साथ ही समाज और पीड़ित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे।

इस अवसर पर दिनेश थापन एडवोकेट, राकेश थापन, गौरव बिश्नोई, संगीता बिश्नोई, राकेश बिश्नोई (प्रेस वाले), सुनील बिश्नोई, अंकुश बिश्नोई, सभासद बृजमोहन बिश्नोई उर्फ बल्ली, संजय बिश्नोई, शरद थापन सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे।

ग्राम पंचायतों में औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की खुली पोल

एडीओ पंचायत ने पंचायत घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी व सामुदायिक शौचालय का लिया जायजा

स्योहारा/बिजनौर (सब का सपना):- विकास खंड स्योहारा की ग्राम पंचायतों में मंगलवार को एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने औचक निरीक्षण कर विभिन्न विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पंचायत घर से लेकर विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी, आरआरसी सेंटर, सामुदायिक शौचालय एवं ग्राम सचिवालय की व्यवस्थाएं परखी गईं। एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत लाम्बाखेड़ा स्थित पंचायत घर का निरीक्षण किया। यहां पंचायत सहायक भव्या सिंह ग्रामीणों से संबंधित योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन करती हुई मिलीं। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों तथा प्राथमिक विद्यालय लाम्बाखेड़ा का परख ऐप के माध्यम से निरीक्षण किया गया। विद्यालय में कुल 128 छात्र-छात्राएं पंजीकृत मिले, जिनमें निरीक्षण के समय 86 बच्चे उपस्थित थे। इनमें 32 बालक और 54 बालिकाएं शामिल रहीं। विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की गई, जो संतोषजनक पाई गई। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सुनील कुमार, चार सहायक अध्यापक तथा तीन रसोइया कार्यरत हैं। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि सभी का जुलाई 2026 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत माढूपुरा की डिजिटल लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सचिव माधव राणा को पुस्तकालय की शेष सभी व्यवस्थाएं जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) का भी जायजा लिया गया। वहीं ग्राम पंचायत मुबारकपुर मंधु में सामुदायिक शौचालय एवं ग्राम सचिवालय का निरीक्षण किया गया, जहां पंचायत सहायक रिंकी उपस्थित मिलीं। औचक निरीक्षण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार भी एडीओ पंचायत के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने तथा शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

खुशनुमा की मौत में नया मोड़, वायरल वीडियो ने खड़े किए कई सवाल

मुझे बचा लो, ये मुझे जलाकर मार देंगे मौत से पहले का बताया जा रहा वीडियो वायरल, पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट नहीं

नगीना/बिजनौर (सब का सपना):- नूरसराय में 25 वर्षीय खुशनुमा जहां की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो सामने आने के बाद मामला और उलझ गया है। वीडियो में रोते हुए महिला कथित रूप से कह रही है कि मुझे बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, ये मुझे जलाकर मार देंगे। वीडियो सामने आने के बाद मृतका की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब आठ बजे नूरसराय निवासी जाकिर मुल्तानी की पत्नी खुशनुमा जहां की मौत की सूचना व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल हुई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विकास कुमार महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उस कमरे का निरीक्षण किया, जहां खुशनुमा बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। पूछताछ में ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस को बताया कि खुशनुमा को दौरे पड़ते थे और मृत्यु से पहले भी उसे दौरा पड़ा था। इधर, रात करीब नौ बजे मृतका का भाई मोहम्मद नईम नगीना पहुंचा। उसने पुलिस को अपनी बहन की मौत संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की। थाना प्रभारी के अनुसार नईम ने ससुराल पक्ष पर खुशनुमा को परेशान करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर मोर्चरी भेज दिया।

मौत से पहले का बताया जा रहा वीडियो वायरल

सोमवार शाम सोशल मीडिया पर खुशनुमा का मोबाइल के फ्रंट कैमरे से बनाया गया एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वह रोते हुए मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। कथित वीडियो में वह चार पहिया वाहन की मांग का जिक्र करते हुए कहती है कि वह गाड़ी कहां से लाए। साथ ही अपने पिता के इंतकाल और मां के इद्दत में होने की बात भी कहती है तथा बार-बार उसे बचाने की गुहार लगाती सुनाई देती है। वायरल वीडियो के साथ मृतका के भाई नईम के हवाले से ससुराल पक्ष पर चार पहिया वाहन की मांग करने, कमरे में बंद कर मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि खुशनुमा करीब सात माह से मायके में रह रही थी और समझौते के बाद 29 अगस्त को ही उसे ससुराल नगीना भेजा गया था। इसके अगले दिन ही उसकी मौत की सूचना मायके वालों को मिली।

बीमारी, आत्महत्या या हत्या? जांच पर टिकी निगाहें

खुशनुमा की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई, उसने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। वायरल वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया है, हालांकि वीडियो की सत्यता, उसकी रिकॉर्डिंग का समय और उसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। थाना प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। बिसरा प्रिजर्व कर जांच के लिए लैब भेजा गया है। फिलहाल मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। परिजनों की शिकायत मिलने पर जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल वैन ने सगे भाइयों को रौंदा मासूमों की जिंदगी दांव पर लगा भागा स्कूल संचालक

धामपुर/बिजनौर (सब का सपना):- सड़क पर दौड़ती लापरवाही ने एक बार फिर दो परिवारों के चिरागों को बुझाने की कोशिश की है। धामपुर के नगीना रोड पर एक तेज रफ्तार स्कूल वैन ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि देखने वालों की रूह कांप गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों भाई लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। खुद के बच्चे को बचाया, बाकी को तड़पता छोड़ा इस पूरी घटना में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के वक्त वैन में जे.के. पब्लिक स्कूल के संचालक का खुद का बच्चा भी मौजूद था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, स्कूल संचालक ने बाकी घायल बच्चों या सड़क पर तड़प रहे बाइक सवार भाइयों की सुध लेने के बजाय, सिर्फ अपने बच्चे को उठाया और मौके से रफूचक्कर हो गया। वैन का ड्राइवर भी गाड़ी छोड़कर तुरंत वहां से भाग निकला। एम्स से लौट रहे थे भाई, अस्पताल में जिंदगी की जंग पीड़ित पिता दिग्विजय सिंह (निवासी काशीपुर) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके दो बेटे अभिषेक (25 वर्ष) और रितिक (23 वर्ष) ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल से अपनी मोटरसाइकिल (UK018D-4221) पर वापस घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे सांई मंदिर के पास गलत साइड से आ रही जे.के. पब्लिक स्कूल की वैन (UP020T-4602) के ड्राइवर ने लापरवाही से उन्हें सामने से उड़ा दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों भाइयों के हाथ-पैर की हड्डियां टूट गई हैं और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों का इलाज काशीपुर के के.आर. हॉस्पिटल में चल रहा है, जहाँ वे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस से सख्त कार्रवाई की गुहार घटना के बाद गुस्साए पिता ने कोतवाली धामपुर में तहरीर देकर जे.के. पब्लिक स्कूल के संचालक और वैन ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि पुलिस इन बेपरवाह 'नौनिहालों के ठेकेदारों' पर क्या एक्शन लेती है!

6 सब का सपना
हिंदी दैनिक
अमरोहा/फतेहपुर
अमरोहा
बुधवार 02 सितंबर 2026
www.sabkasapna.com

बारिश में धंसी मिट्टी, कच्चे मकान पर गिरा महुआ का पेड़, गाय की मौत

फतेहपुर (सब का सपना):- जिलें के धाता नगर पंचायत के वार्ड नंबर-14 रमाबाई नगर के नगरूवा गांव में मंगलवार सुबह लगातार बारिश के बीच हादसा हो गया। बारिश से मिट्टी धंसने के कारण महुआ का पेड़ उखड़कर कच्चे मकान पर जा गिरा। मकान में बंधी गाय पेड़ और मलबे के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नगरूवा निवासी सुषमा देवी पत्नी संतोष सिंह ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे अचानक मिट्टी खिसकने से पेड़ मकान पर गिर गया। हादसे की जानकारी पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पेड़ व मलबा हटाकर गाय को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पीड़िता के अनुसार मृत गाय की कीमत करीब 70 हजार रुपये थी। सभासद दुर्ग विजय सिंह ने पुलिस, नगर पंचायत, पशु चिकित्सा विभाग और लेखपाल को सूचना दी। पशु चिकित्सा अधिकारी प्रवीण सचान ने बताया कि नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है।

वायरल बुखार के मरीज बढ़े, सीएचसी में 117 की ओपीडी

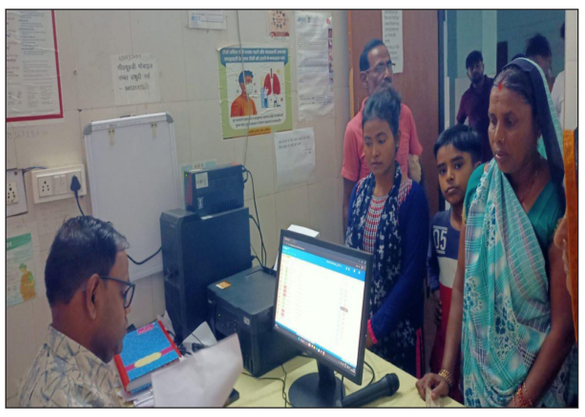

फतेहपुर (सब का सपना):- जिले के धाता प्राथमिक स्वास्थकेंद्र में बदलते मौसम और लगातार हो रही बारिश के बीच वायरल बुखार समेत अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 117 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई। अस्पताल में मरीजों की जांच और उपचार के लिए चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। सीएचसी में मरीजों की आवश्यकतानुसार सीबीसी, केएफटी, आईएफटी, लिपिड प्रोफाइल सहित बुखार से संबंधित जांच की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी के दौरान चिकित्सक डॉ. प्रह्लाद सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार और डॉ. लालबहादुर मरीजों का परीक्षण करते नजर आए। स्वाइन फ्लू, मलेरिया और डेंगू से बचाव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कुमार से जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बुखार के मरीजों की जांच कर आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। चिकित्सक ने लोगों से बारिश के मौसम में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने, आसपास पानी जमा न होने देने तथा बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर समय से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को मच्छरों से बचाव और स्वच्छ पेयजल के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

यूकेलिप्टिस की लकड़ी से भरी पिकअप पकड़ी, वन विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप

नजीबाबाद/बिजनौर (सब का सपना):- बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद की साहूवाला वन रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से यूकेलिप्टिस के पेड़ों के कटान का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने अकबराबाद क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरी एक पिकअप को कब्जे में लिया है। प्रारंभिक जांच में बरामद लकड़ी को आरक्षित वन क्षेत्र से किए गए अवैध कटान से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया है कि वन विभाग की टीम को क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई यूकेलिप्टिस की लकड़ी के संबंध में जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने अकबराबाद क्षेत्र में निगरानी करते हुए लकड़ी से भरी पिकअप को पकड़ लिया। वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर वन विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। विभाग के संज्ञान में मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और संदिग्ध लोगों के नाम आने की बात सामने आई है। अब जांच टीम बरामद लकड़ी के स्रोत, कटान स्थल और पिकअप में लकड़ी लाने वाले लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद अवैध कटान में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट होगी। यदि जांच में आरक्षित वन क्षेत्र से पेड़ों का अवैध कटान साबित होता है तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, उसकी भूमिका के आधार पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

भाजपा ने मंडल से बूथ तक संगठन को मजबूत करने की बनाई रणनीति

जिला कार्यालय में मंडल कार्यसमिति, बूथ समिति एवं शक्ति केंद्र संयोजकों के सत्यापन को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक

फतेहपुर (सब का सपना):- भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मंडल कार्यसमिति, बूथ समितियों एवं शक्ति केंद्र संयोजकों के सत्यापन अभियान को लेकर महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने की। मंच पर पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रभुदत्त दीक्षित, दिनेश बाजपेई, प्रमोद द्विवेदी एवं आशीष मिश्रा समेत जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल एवं सुशील मौर्य मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश संगठन द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के तहत मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर विस्तृत मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत बूथ संगठन है। बूथ संगठन जितना मजबूत होगा, पार्टी का जनाधार उतना ही व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान को महज औपचारिकता न मानते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के अभियान के रूप में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन वर्षभर जनता के बीच सेवा, संवाद और संगठन विस्तार के लिए कार्य करता है। मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ संगठन पार्टी की मजबूत कड़ी हैं, जिनके माध्यम से संगठन की विचारधारा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। बताया कि मंडल कार्यसमिति एवं शक्ति केंद्र संयोजकों के सत्यापन की बैठक 2 सितंबर तथा बूथ समितियों के सत्यापन की बैठकें 3 एवं 4 सितंबर को आयोजित की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया में मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी एवं संयोजक तथा संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। बैठक में प्रत्येक शक्ति केंद्र के अंतर्गत आने वाली बूथ समितियों के सदस्यों की भौतिक उपस्थिति में बैठक कर सत्यापन करने तथा बूथ प्रभारी एवं पालक की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जहानाबाद मंडल अध्यक्ष नितिन ओमर, अमौली के देवेंद्र अवस्थी, देवमई के आशुतोष अग्निहोत्री, खजुहा के रोहन श्रीवास्तव, बिंदकी नगर के पूरन सिंह, मलवां की श्वेता शुक्ला, तेलियानी के अरुण लोधी, जोनिहा के कोमल सिंह, नगर उत्तरी के संजय श्रीवास्तव, नगर दक्षिणी के दिनेश प्रसाद गुप्ता, भिटौरा के सुभाष पाण्डेय, हसवा के सुरेंद्र मौर्य, बहुआ के संजय सिंह, गाजीपुर के विनोद पाण्डेय, असोथर के रामहेत निषाद, हुसैनगंज के श्रीकांत अवस्थी, धाता के राजू लोधी, हथगाम के गणेशीलाल साहू, अल्लीपुर के राणा प्रताप सिंह, खागा के ब्रजेश सिंह, विजयीपुर की प्रीति सिंह, खखरेरू के गया पाल एवं धाता के रामनारायण शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का संचालन जिला मंत्री विमलेश पाण्डेय ने किया।

इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी से जिला उपाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, रेखा मिश्रा, सुनीता गुप्ता, अर्चना त्रिपाठी, मोना शुक्ला, साधना सिंह, रेखा सरोज, कुलदीप भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह, ओम मिश्रा, प्रवीण सिंह, प्रसून तिवारी, शिवकांत तिवारी, अखिलेश, अंतुल अवस्थी, कमलेश योगी, एवं सुनिधि तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

योगी सरकार का लक्ष्य: सरकारी नौकरियों में योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं में ऐसी पारदर्शी और निष्पक्ष चयन व्यवस्था को मजबूत करना है, जिसमें योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और योग्य अभ्यर्थियों को अपनी प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह ख के अधिकारियों की भर्ती के लिए अपनाई गई नई चयन प्रक्रिया इसी सोच का परिणाम है। लंबे अंतराल के बाद बोर्ड में 40 अधिकारियों की नियमित भर्ती पूरी होने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी। मंगलवार को वन मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बोर्ड में नवचयनित 40 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी सीधे पर्यावरण और लोगों के स्वस्थ जीवन से जुड़ी है। अधिकारी अपनी तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ करें। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने तथा विभागीय कार्यप्रणाली के साथ मैदानी स्तर की चुनौतियों को समझने के निर्देश दिए। बोर्ड में समूह ख के 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी समेत कुल 40 अधिकारियों का चयन किया गया है। इनमें 21 अधिकारी विभिन्न आइआइटी से शिक्षित हैं, जबकि अन्य ने देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है। चयनित अधिकारियों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं। यह भर्ती चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव के बाद हुई है। पहले बोर्ड में समूह ख के अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से साक्षात्कार के आधार पर होती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1995 की पुरानी विनियमावली में संशोधन कर चयन प्रक्रिया को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आधारित द्विस्तरीय व्यवस्था में बदला गया।

नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा को 85 प्रतिशत और साक्षात्कार को 15 प्रतिशत अंक का वेटेज दिया गया, जिससे शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को चयन का प्रमुख आधार बनाया गया। इन अधिकारियों को सीधे क्षेत्र में तैनाती देने के बजाय पहले एक माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत एक सप्ताह का कार्यक्रम आइआइएम, लखनऊ में आयोजित हो रहा है।

स्थायी समिति में जनहित के मुद्दों पर बड़ा मंथन, डेंगू से अतिक्रमण तक अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को राजधानी से जुड़े कई ज्वलंत जनहित के मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। डेंगू-मलेरिया और स्वाइन फ्लू की रोकथाम से लेकर अवैध प्ले स्कूल, सड़कों पर अतिक्रमण, अवैध खाने के ठेले, खुले में तंदूर, बेसहारा पशु, पार्कों की बदहाल व्यवस्था, प्रदूषण और स्वच्छता जैसे मुद्दे बैठक में प्रमुखता से उठे। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि समिति जनहित के मुद्दों पर लोकतांत्रिक संवाद का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों को अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव रखने का पूरा अवसर दिया गया और अधिकारियों को उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डेंगू-मलेरिया पर फॉगिंग और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर सत्या शर्मा ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान में संबंधित क्षेत्र के पार्षदों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान और समाधान तेजी से हो सके। स्वाइन फ्लू को लेकर निगम अलर्ट दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों का संज्ञान लेते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष ने नागरिकों को बीमारी से बचाव और जरूरी सावधानियों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निदेर्शों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अवैध प्ले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी अवैध रूप से संचालित प्ले स्कूलों का मुद्दा भी बैठक में उठा। सत्या शर्मा ने अधिकारियों से ऐसे संस्थानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़कों पर अवैध ठेले और खुले तंदूर पर शिकंजा सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अवैध रूप से संचालित खाने के ठेलों तथा खुले में तंदूर के इस्तेमाल को लेकर भी समिति ने गंभीरता दिखाई। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे स्थानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा अतिक्रमण और नागरिक सुरक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। आवारा पशुओं की समस्या पर नई गौशालाओं का प्रस्ताव सड़कों पर घूम रहे आवारा और बेसहारा पशुओं को लेकर सत्या शर्मा ने कहा कि यह समस्या यातायात के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर नई गौशालाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि सड़कों पर घूम रहे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। प्रस्ताव पारित करना ही लक्ष्य नहीं, कार्रवाई भी दिखनी चाहिए सत्या शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्थायी समिति की बैठक में उठाए गए जनहित के मुद्दे केवल चर्चा तक सीमित न रहें। संबंधित विभाग समयबद्ध कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, जनस्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा, अतिक्रमण और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े विषय सीधे दिल्लीवासियों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। निगम इन विषयों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

योगी सरकार का हॉट कुक्ड मील बना 33 लाख नौनिहालों का सुरक्षा कवच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाल स्वास्थ्य और कुपोषण मुक्त भविष्य की नींव को मजबूत करते हुए योगी सरकार की 'हॉट कुक्ड मील' योजना आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदल रही है। 'सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0' अभियान के तहत प्रदेश के करीब 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के 32.88 लाख से अधिक नौनिहालों को प्रतिदिन ताजा, गर्म और संतुलित भोजन परोसा जा रहा है। यह पहल न केवल बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ आहार की आदत डाल रही है, बल्कि राज्य में शिशु स्वास्थ्य मानकों को भी नए आयाम दे रही है। साप्ताहिक मेन्यू में विविधता और गुणवत्ता की गारंटी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मानकों के अनुसार, बच्चों की थाली में हर दिन विविधता का ध्यान रखा गया है। मेन्यू में रोटी, चावल, दाल और मौसमी हरी सब्जियों से भरपूर स्वादिष्ट तहरी शामिल है। भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर सरकार का रुख बेहद सख्त है। सघन जांच प्रक्रियाः कोटेदार से मिलने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता की सख्त जांच के साथ-साथ सब्जियों को पकाने से पहले कई बार धोने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल (टेस्टिंग रोस्टर): बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व दो वयस्कों–जैसे शिक्षक, रसोइया या माता समिति के सदस्यों द्वारा रोजाना इसका स्वाद व गुणवत्ता जांची जाती है। प्रति बच्चा 70 ग्राम पोषणः प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न से तैयार पोषाहार सुनिश्चित किया जा रहा है। सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और विभागीय तालमेल अपर मुख्य सचिव (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) लीना जौहरी के अनुसार, 1.45 लाख को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'पीएम पोषण योजना' की रसोइयों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं, 0.44 लाख नॉन-को-लोकेटेड केंद्रों पर स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की मदद से रसोई बर्तन व गैस चूल्हे उपलब्ध कराकर निर्बाध भोजन व्यवस्था संचालित की जा रही है।

डीएम-एसपी ने शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अमरोहा (सब का सपना):- जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 नितिन गौड़ की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव की उपस्थिति में कलक्ट्रेट सभागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री रामडोल शोभायात्रा के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों एवं आयोजकों से समस्याओं की जानकारी लेते हुए सुझाव प्राप्त किए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्व को परंपरागत तरीके से शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। अनावश्यक रूप से कोई नई परंपरा न डाली जाए। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि के कोई सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें। किसी समस्या अथवा विवाद की जानकारी तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाएं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शोभायात्रा एवं जुलूस के निर्धारित मार्गों का पूर्व में स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराई जाएं। शोभायात्रा मार्ग एवं मंदिरों के आसपास विशेष साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मार्गों पर गड्ढे एवं जलभराव न हो, साफ-सफाई एवं पथ प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे तथा किसी प्रकार का अवरोध न हो। विद्युत विभाग को जर्जर एवं लटकते तारों को दुरुस्त कराने तथा आवश्यक स्थानों पर विद्युत पोलों को सुरक्षित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने त्योहार के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री रामडोल शोभायात्रा को पूर्व में संपन्न हुए पर्वों की तरह सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। शोभायात्रा निर्धारित एवं परंपरागत मार्गों से ही निकाली जाए तथा ऐसा कोई कार्य न किया जाए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा हो। उन्होंने आयोजकों से शोभायात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने तथा पर्याप्त वॉलेंटियर्स लगाने की अपील की। साथ ही डीजे का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा आपत्तिजनक अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री से बचने को कहा। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों का पूर्व भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। शोभायात्रा के प्रमुख मार्गों एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी भ्रामक अथवा आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो या ऑडियो को बिना सत्यापन के साझा न करें तथा ऐसी सामग्री की सूचना तत्काल पुलिस-प्रशासन को दें। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी डॉ0 नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने श्री रामडोल शोभायात्रा के निर्धारित मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर साफ-सफाई, सड़क, विद्युत, पथ प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को शोभायात्रा से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, समस्त थाना प्रभारी, आयोजक, शांति समिति के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अन्ना हजारे को वायरल संक्रमण, अस्पताल में भर्ती

मुंबई (एजेंसी)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को वायरल संक्रमण और गंभीर निर्जलीकरण के इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारे के एक सहयोगी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सहयोगी के मुताबिक 89 साल के हजारे को सोमवार को दक्षिण मुंबई स्थित बॉम्बे अस्पताल लाया गया। इससे पहले उन्हें शुरुआती इलाज के लिए अहिल्यानगर जिले के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टर हजारे की स्वास्थ्य स्थिति का विस्तृत आकलन कर रहे हैं, जिसके आधार पर आगे के इलाज के बारे में फैसला लिया जाएगा।

2014 की रैली का चैनल के पास मूल वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं

-आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर मानहानि का मामला किया था दायर

मुंबई (एजेंसी)। जी मीडिया ने महाराष्ट्र में भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत को बताया कि चैनल के पास 2014 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली का मूल वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं है। आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। कुंटे का आरोप है कि राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को जिले के सोनाले गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़कर अपमानजनक बयान दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक रैली के वीडियो साक्ष्य पेश करने के लिए अदालत के समन के जवाब में जी मीडिया ने एक औपचारिक हलफनामा दाखिल कर कहा कि चैनल उक्त फुटेज पेश करने में असमर्थ है। मीडिया नेटवर्क ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रसारण 12 साल से ज्यादा समय पहले हुआ था और मानक ''अनुपालन लॉगिंग'' दिशानिर्देशों के तहत टीवी चैनलों के लिए प्रसारण रिकॉर्ड केवल 90 दिनों तक सुरक्षित रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मीडिया समूह ने कहा कि कार्यक्रम को कवर करने वाले पत्रकार भी अब या तो नौकरी छोड़ चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राहुल गांधी के वकील ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख तय की है।

एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, 15 से ज्यादा घायल

-खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु की पिकअप खड़े ट्रक से टकराई

पलवल (एजेंसी)। हरियाणा के कुंडली-मानसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें 6 की मौत हो गई और कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर उत्तर प्रदेश लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में पिकअप और ट्रक दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एनएचएआई की राहत टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े ट्रक का अंदाजा न लग पाने या अचानक असंतुलन बिगड़ने के कारण पिकअप सीधे उसमें जा घुसी। दुर्घटना में घायल हुए 15 लोगों को तुरंत नजदीकी नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच शुरु कर दी है।

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद एनकाउंटर में मालिक घायल

प्रयागराज (एजेंसी)। यूपी की जिस अवैध पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को विस्फोट हुआ था, उसके मालिक को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसे पैर में गोली लगी है। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। मंगलवार तड़के 4 बजे सैयद सरावां इलाके में मुठभेड़ हुई थी। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले 8 बच्चों समेत 11 लोगों का पोस्टमॉर्टम होगा। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक नौशाद, उसकी पत्नी, बेटे समेत परिवार के 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पत्नी शबाना को हिरासत में भी लिया है।

सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला भारत ने मानने से किया इनकार

विदेश मंत्रालय ने कहा- इस फैसले का भारत की परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा

नई दिल्ली, एजेंसी।
सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय स्थायी मध्यस्थता अदालत के अंतरिम फैसले को भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। भारत ने इस अदालत को अवैध बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के संप्रभु निर्णयों पर फैसला सुनाने का इस अदालत को कोई अधिकार नहीं है। उसने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि को रोकने का हमारा फैसला लागू रहेगा। अपने अंतरिम आदेश में सोमवार को नीदरलैंड के हेग स्थित इस अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ जल-साझाकरण संधि का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत कश्मीर क्षेत्र में निर्माणाधीन एक जलविद्युत संयंत्र पर भी काम को सीमित करे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस अदालत के फैसले का अब या भविष्य में भारत द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसने कहा कि भारत ने कभी भी इस अंतरराष्ट्रीय अदालत को मान्यता नहीं दी है और लगातार कहा है कि इस कथित मध्यस्थता निकाय की स्थापना सिंधु जल सं?धि का सीधा-सीधा उल्लंघन है और वह इसके फैसले को उसी तरह खारिज करता है जैसे पहले की सभी घोषणाओं को करता आया है।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में अपनी किसी भूमिका से इनकार किया था और भारत द्वारा पिछले साल कश्मीर क्षेत्र में दो जलविद्युत परियोजनाओं की जलाशय क्षमता बढ़ाने के काम शुरू करने के बाद कानूनी कार्रवाई का रास्ता पकड़ा था। दोनों देशों के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, उसके बाद से दोनों में तीन युद्ध और छोटे-बड़े कई संघर्ष होने के बावजूद इस संधि पर कोई असर नहीं पड़ा था। वे इस पर अमल करते आ रहे थे। स्थायी मध्यस्थता कोर्ट ने कहा कि सिंधु जल संधि पूरी तरह लागू है और भारत के पास समझौते को समाप्त करने या निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है।
अंतर-सरकारी अदालत ने कहा कि भारत को संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, जिसमें पश्चिमी नदियों पर

उसकी जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन से संबंधित दायित्व भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ अगले साल जुलाई तक यह तय करेगा कि हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत संयंत्रों का निर्माण संधि के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

महिला सशक्तिकरण की वास्तविक शुरुआत घर और शिक्षा से होती है : राज्यपाल पटेल

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक शुरुआत घर और शिक्षा से होती है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा, स्टार्टअप, व्यवसाय और कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रही हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही सोच, अवसर और परिवार का सहयोग मिलना जरूरी है। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल आनंदीबेन पटेल ने विश्वास जताया कि आने वाले सालों में महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता और नेतृत्व के हर क्षेत्र में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि नारी केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की भी शक्ति है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें अवसर के साथ-साथ नेतृत्व और फैसले लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संघ के कार्यों में मातृशक्ति का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। महाना ने कहा कि संघ में महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च है और उनका सहयोग परिवार, सेवा तथा समाज को साथ लेकर चलने की शक्ति प्रदान करता है। आनंदीबेन पटेल ने पुस्तक की लेखिका डॉ. शोभा विजेंद्र को पुस्तक के जरिए महिला सशक्तिकरण के विचारों को समाज तक पहुंचाने और देश के कई हिस्सों में संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी।

सीएम विजय ने इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरे के रूप में राहुल गांधी का किया समर्थन

-तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस के बीच मतभेद की अटकलों पर लगा विराम

हल्द्वानी, एजेंसी।
चेन्नई,(ईएमएस)। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी टीवीके और कांग्रेस के बीच गठबंधन में मतभेद की अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता ताराहाई कथबर्ट ने स्पष्ट किया है कि टीवीके के प्रमुख और सीएम विजय ने इंडिया गठबंधन के पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी का समर्थन किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कथबर्ट ने कहा कि विजय और राहुल गांधी के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। हाल ही में एक सर्वे में विजय को पीएम पद की पसंद में तीसरा स्थान मिलने के बाद टीवीके समर्थकों के उत्साह में कुछ बातें सामने आई थीं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वे बातें कार्यकर्ताओं का उत्साह थीं, पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं। टीवीके आधिकारिक रूप से राहुल गांधी को ही 2029 के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखती है।
इसके बाद टीवीके ने शीर्ष पद के लिए विजय का नाम आगे बढ़ाया, जिससे कांग्रेस ने गठबंधन छोड़ने की धमकी दी, जब तक कि वह इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर राहुल गांधी का समर्थन न करें। उन्होंने कहा कि कुछ हलकों में विजय के प्रधानमंत्री बनने की जो बातें हो रही थीं, वे टीवीके कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण थीं और वे नेतृत्व के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती थीं। उन्होंने कहा कि सीएम विजय ने राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर चुना है। वे इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विजय ने राहुल गांधी को चेन्नई में अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन्हें अपना भाई कहा था। राहुल गांधी ने भी टीवीके सरकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इस बीच कथबर्ट ने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु में स्वतंत्र रूप से विस्तार कर रही है और टीवीके के अधीन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक और स्वायत्त पार्टी है। उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में दर्ज एफआईआर को बीजेपी की राजनीतिक घबराहट बताया था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राहुल गांधी की व्यापक जन-स्वीकार्यता से डरी हुई है और वे 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे।

मणिपुर में केंद्र सरकार ने राज्य में जनगणना कराने पर लगाया ब्रेक

-जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करने की मांग पर लिया फैसला

इम्फाल, एजेंसी।
जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में केंद्र सरकार ने राज्य में जनगणना अभियान को स्थगित करने का फैसला लिया है! यह फैसला मणिपुर के नागरिक संगठनों की उस मांग के बाद लिया गया, जिसमें जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने की मांग की गई थी। जनगणना के तहत राज्य में घरों की सूची बनाने का काम 1 सितंबर से शुरू होना था।
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक में मणिपुर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान राज्य के लोगों की ओर से जनगणना को टालने और पहले एनआरसी लागू करने की मांग पर भी चर्चा हुई। बैठक में मणिपुर के लोगों की भावनाओं और उनकी आकांक्षाओं को

देखते हुए राज्य में प्रस्तावित जनगणना को फिलहाल टालने पर सहमति बनी।
मणिपुर में एनआसी लागू करने की मांग मुख्य रूप से मैतेई और नगा समुदायों की ओर से उठाई गई है। इन समुदायों में आशंका है कि एनआरसी के बिना जनगणना कराने से राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हो सकता है। उनका आरोप है कि पड़ोसी म्यांमार से अवैध प्रवासियों के आने के कारण राज्य की आबादी के स्वरूप में बदलाव हो रहा है। म्यांमार से आने वाले कथित अवैध प्रवासियों के कुकी समुदाय से जातीय संबंध होने की बात भी कही जाती रही है। बैठक के बाद सीएम वाई. खेमचंद सिंह ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि केंद्र ने मणिपुर के लोगों की आवाज सुनी और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में फैसला लिया। सीएम ने बीजपी अध्यक्ष नितिन नबीन का भी मणिपुर के लोगों की मांगों को पूरा कराने में लगातार समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। बता दें मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से घाटी वाले इलाकों में रहता है, जबकि कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी जिलों में बड़ी संख्या में रहते हैं। इस हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए। लगातार जारी जातीय संघर्ष और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। करीब एक साल बाद 4 फरवरी को इसे हटा दिया गया था।

जयराम का मोदी सरकार पर हमला: फर्ज़ी सुर्खियों में व्यस्त पीएम

-महंगाई ने छीनी घर बनाने की उम्मीद

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोलकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी सुर्खियां बनाने में व्यस्त हैं, जबकि देश को बढ़ती महंगाई का ज़बरदस्त झटका लग रहा है। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि मोदी सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से लोगों को गुमराह कर रही है और हर हफ़्ते देश को कीमतों का नया झटका दे रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई अब केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि बढ़ती मंहगाई ने आम आदमी के घर बनाने के सपने को भी छीन लिया है। गरीब और मध्यम वर्ग को घर बनाने से लेकर बिजली के सामान तक हर चीज की बढ़ती कीमतों का ज़ोरदार झटका महसूस हो रहा है। रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस महासचिव रमेश ने बताया कि तांबे के तार की कीमत 850 से बढ़कर 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, और एल्युमीनियम की कीमत भी लगभग दोगुनी हो गई है। इससे 1,000 वर्ग फुट के घर में वायरिंग का खर्च 50,000 रुपये से बढ़कर करीब 1 लाख हुआ है।
कांग्रेस नेता रमेश ने दावा किया कि सोलर पैनल 10-15 प्रतिशत महंगे हो गए हैं, जबकि पंखों, फॉल्स सीलिंग और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे घरेलू उपकरणों की कीमतों में भी 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। एलईडी और हैलोजन लाइटें भी लगभग 20 प्रतिशत महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि स्विच, सॉकेट, मेन-लाइन

केबल, टाइल्स और लेबर चार्ज जैसे घर बनाने से जुड़े हर खर्च में इजाफा हुआ है। कांग्रेस सांसद रमेश ने मोदी सरकार पर अहंकार और आंकड़ों की बाजीगरी से लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि महंगाई आम लोगों की जेब पर हर तरफ से भारी चोट कर रही है।

सीजेपी के फिर आंदोलन के ऐलान से डरी सरकार, बात करने 2000 किमी दूर पहुंच गई

नई दिल्ली, एजेंसी।
5 सितंबर को दिल्ली में फिर आंदोलन का ऐलान कर चुकी कॉकरोच जनता पार्टी को मनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जंतर-मंतर पर एक महीने तक आंदोलन करके सरकार को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने पर मजबूर कर चुकी सीजेपी ने अब इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वॉर्टर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है। सरकार ने सीजेपी को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सीजेपी नेता से बातचीत करने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर पुडुचेरी तक गया। सीजेपी ने नए आंदोलन की जो तारीख चुनी है वह दिल्ली में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन से दूर नहीं है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि जब रूस, चीन समेत करीब 20 देशों के प्रतिनिधि-राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आएं तो सड़कों

पर किसी तरह की अशांति नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने सोमवार रात केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को जहां सकारात्मक बताया तो वहीं उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि सीजेपी को मनाने के लिए सरकार कितनी कोशिशें कर रही है। सौरभ ने बताया कि सरकार की तरफ से एक उच्च स्तरीय कमिटी उनसे लगातार संपर्क में है। यहां तक कि वह पुडुचेरी में अपने घर चले गए थे तो यह कमिटी वहां भी पहुंचा और तीन बार उनके बीच केसों को वापस लिए जाने और मुआवजे को लेकर बातचीत हुई। दास ने संकेत दिया कि सरकार और सीजेपी के बीच समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसके तहत अब सरकार ने यह कदम उठाया है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर सीजेपी सरकार को दबाव में लाने में कामयाब रही? माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि सितंबर की शुरुआत में दिल्ली में कोई आंदोलन हो जब ब्रिक्स बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियां अपने चरम पर हैं। माना जा रहा है कि एफआईआर रद्द कराए जाने के बाद सरकार मुआवजे पर भी जल्द कोई ऐलान करके सीजेपी से 5 सितंबर वाले प्रदर्शन की घोषणा को वापस लेने को कह सकती है।

फडणवीस का कांग्रेस पर हमला : महिला आरक्षण, सीजेपी और एनजीओ पर सवाल

पुणे, एजेंसी।
महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी कर पूछा कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा को मौके क्यों नहीं दिए गए और क्या कांग्रेस महिलाओं को मौका देने के पक्ष में है। सीएम फडणवीस ने कांग्रेस पर 2023 में परिसीमन प्रावधानों वाले महिला आरक्षण कानून का समर्थन करने के बावजूद अब उसका विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा 2029 तक महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत

आरक्षण सुनिश्चित करेगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीजेपी के कांग्रेस से गहरे संबंधों का दावा किया। उन्होंने सीजेपी आंदोलन को कांग्रेस जिताओ प्रोग्राम बताकर कहा कि यह कोई छोटा समूह नहीं, बल्कि इसके पीछे कई चेहरे और कांग्रेस से जुड़े लोग काम कर रहे हैं जो नए नामों से सामने आ रहे हैं। सीएम फडणवीस ने भारत जोड़ो अभियान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले यह अभियान कांग्रेस का अपना नहीं था, बल्कि इसमें लगभग 180 अलग-अलग एनजीओ शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से अधिकतर एनजीओ को यूपीए सरकार ने ही अर्बन नक्सल करार दिया था। फडणवीस के अनुसार, इन संस्थाओं को कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इन एनजीओ की कोई जवाबदेही नहीं थी, ये चुनाव नहीं लड़ते थे और रोज़ झूठ फैलाते थे, जिसका भाजपा को जवाब देना पड़ता था।

दिल्ली में मसौदा मतदाता सूची से 47.5 लाख नाम हटाए गए, सबसे ज्यादा बुराड़ी से

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली में 70 विधानसभा सीट की मसौदा मतदाता सूची के मुताबिक बुराड़ी में सबसे ज्यादा 1.67 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा 47.85 फीसदी नाम तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हटाए गए हैं। इसके बाद ओखला 45.33 फीसदी, कस्तूरबा नगर 44.03 फीसदी, और बदरपुर 42.67 फीसदी हैं। संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा नाम बुराड़ी में हटाए गए हैं, जो उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद ओखला में 1.63 लाख, बदरपुर में 1,46,673, विकासपुरी में 1,46,225 और रिठाला में 1.06 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक संख्या के आधार पर सबसे कम 22,855 नाम दिल्ली कैंट में हटाए गए हैं।
इसके बाद रोहिणी 24,888, शकूर बस्ती 27,233, राजौरी गार्डन 30,856 और मटिया महल 32,099 हैं। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम 16.5 फीसदी नाम रोहिणी में हटाए गए हैं। इसके बाद शकूर बस्ती 18.74 प्रतिशत, राजौरी गार्डन 20.86 प्रतिशत, मंगोलपुरी 21.24 प्रतिशत और मटिया महल 24.5 प्रतिशत हैं। जिला स्तर पर मसौदा मतदाता सूची से सबसे ज्यादा 6.79 लाख नाम दक्षिण-पूर्वी दिल्ली जिले में हटाए गए हैं। वहीं, नई दिल्ली जिले में सबसे कम 60,170 नाम हटाए गए हैं। पूर्वी दिल्ली 5.70 लाख, उत्तर-पूर्वी दिल्ली 5.43 लाख, दक्षिणी दिल्ली 5.19 लाख और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली 3.71 लाख में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
एसआईआर के बाद सोमवार को जारी दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची में मौजूदा 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। मसौदा सूची जारी होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया है, जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को जारी की जाएगी।

हिमांशी खुराना ने लगाई आसिम पर आरोपों की झड़ी

हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के बीच जुबानी जंग चल रही है। यह विवाद बीते कुछ दिनों में ही काफी बढ़ गया है। आसिम की पोस्ट के बाद अब हिमांशी ने सोशल मीडिया के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जवाब दिया है।

हिमांशी ने पोस्ट में क्या लिखा?

हिमांशी खुराना ने सोशल मीडिया के जरिए आसिम का नाम लिए बिना उनपर निशाना साधा है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने कभी धर्मांतरण का मुद्दा नहीं उठाया। इसके साथ ही आसिम द्वारा अपने स्वास्थ को लेकर रही की गई बातों पर भी प्रतिक्रिया दी। हिमांशी ने लिखा - मैंने किसी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप नहीं लगाया। मैंने हमेशा सार्वजनिक रूप से अपनी निजी जीवन को साझा करते समय सम्मान और सावधानी बरती है। हर चीज चाहे वह बिग बॉस का अनुभव हो, मेरी आध्यात्मिक यात्रा हो, या मेरी सेहत से जुड़े मामले हों, मैंने सम्मान बनाए रखा। मैंने अपने जीवन के इन पहलुओं को ईमानदारी से साझा किया है। कभी भी किसी का अपमान करने के लिए उपयोग नहीं किया। मैंने अपना पक्ष हमेशा मजबूती के साथ रखा है।

हेल्थ पर की गई टिप्पणी पर बोलीं

आसिम रियाज ने हिमांशी की हेल्थ से जुड़ी भी कई बातें कहीं थीं। इन पर हिमांशी ने कहा, 'जहां तक मेरे स्वास्थ्य का मज़ाक उड़ाया जाता है और मेरे संघर्षों पर सवाल किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अब एक सीमा तय करने का समय आ गया है। मुझे भी सब कुछ बता देना चाहिए।'

सारे सबूत मेरे पास भी हैं

आगे हिमांशी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'अगर हम सबूतों की बात करने जा रहे हैं, तो चलिए सब पर बात करते हैं। मेरे पास मेरे साथ हुई हिंसा से संबंधित तथ्य और सबूत हैं। उम्मीद है आपको 27.11.23 की वह सुबह याद होगी, मैं उसे भी साझा करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, तो अब मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो आपकी तथाकथित छवि बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ छुपाती रहूंगी, या बार-बार अपमानित और अनादर किए जाने पर भी चुप रहूंगी।'

लोगों ने आपकी गंदगी को छुपाया

हिमांशी खुराना ने अप्रत्यक्ष रूप से आसिम रियाज पर निशाना साधा। उन्होंने आगे लिखा, 'अलग-अलग प्रोडक्शन हाउस और चैनल के लोगों ने आपकी गंदगी को छुपाया, लेकिन मैं अब उनके जैसी नहीं हूं। मैंने अपनी गरिमा बनाए रखी है और सम्मान दिखाया है, और बदले में मैं भी यही उम्मीद करती हूं। अगर उस सम्मान का प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो मेरे पास अब चुप रहने का कोई कारण नहीं है। अगर आप 'सबूत' का खेल खेलना चाहते हैं, तो चलिए इसे ईमानदारी से खेलते हैं। तथ्यों, जवाबदेही और पूरी सच्चाई के साथ।' इससे पहले आसिम रियाज ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हिमांशी को सभी आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी हिमांशी को धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने हिमांशी की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह भी बताई थी।

24 साल बाद टीवी पर होस्ट बनकर लौट रहीं माधुरी दीक्षित

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने लंबे फिल्मी करियर में एक्टिंग और डांस से तो दर्शकों का दिल जीता ही है, अब वह एक नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। वह जल्द ही टीवी के लोकप्रिय क्विज शो के मराठी वर्जन 'कोण होणार करोडपती' को होस्ट करती नजर आएंगी। यह शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के लोकप्रिय फॉर्मेट पर आधारित है। खास बात यह है कि माधुरी करीब 24 साल बाद एक बार फिर टीवी होस्टिंग की दुनिया में वापसी कर रही हैं। शो को लेकर वह काफी उत्साहित हैं, और उन्होंने बताया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट की तरफ सबसे ज्यादा कंटेस्टेंट्स की कहानियों और उनके सपनों ने आकर्षित किया। शो में शामिल होने की वजह बताते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा, ''कोण होणार करोडपती' सिर्फ सवालों के जवाब देकर पैसे जीतने वाला शो नहीं है, बल्कि यह लोगों के आत्मविश्वास और सपने देखने की हिम्मत से भी जुड़ा है। मुझे सबसे ज्यादा उत्साह इस बात का है कि मैं कंटेस्टेंट्स की कहानियों और उनके सपनों के जरिए उनसे जुड़ पाऊंगी। लोगों की जिंदगी के बारे में जानना और उनके सपनों को समझना मुझे इस शो का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है।'' माधुरी ने एक्टिंग और होस्टिंग के बीच के अंतर के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, ''एक अभिनेता को कैमरे के सामने किसी किरदार में ढलना पड़ता है, जबकि होस्ट के तौर पर वह खुद रह सकता हैं। इस शो में दर्शक मेरा स्वाभाविक अंदाज देखेंगे। मैं कंटेस्टेंट्स के सामने बैठकर उनकी जिंदगी के बारे में बात करूंगी और उनकी बातें सुनूंगी।''

'कोण होणार करोडपती' के जरिए माधुरी करीब 24 साल बाद टीवी होस्टिंग में वापसी कर रही है। इससे पहले वह 'कहीं ना कहीं कोई है' नाम के टीवी शो को होस्ट कर चुकी हैं। हालांकि, इसके बाद उन्होंने फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया।

मराठी 'केबीसी' फॉर्मेट को माधुरी से पहले सचिन खेडेकर, स्वप्निल जोशी और नागराज मंजुले जैसे कलाकार होस्ट कर चुके हैं। शो के मेकर्स ने इसी महीने 'कोण होणार करोडपती' का पहला प्रोमो भी जारी किया था। इसमें माधुरी पारंपरिक महाराष्ट्रीयन अंदाज में नजर आई थीं। उनके इस लुक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। प्रोमो सामने आने के बाद से ही शो को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माधुरी के इस नए सफर की जानकारी देते हुए मेकर्स ने बताया था कि माधुरी को 'कौन बनेगा करोड़पति' के मराठी वर्जन 'कोण होणार करोडपती' को होस्ट करने के लिए चुना गया है। उन्होंने शो के प्रोमो की शूटिंग पूरी कर ली है और इसे हिंदी 'कौन बनेगा करोड़पति' के प्रीमियर एपिसोड के साथ जोड़े जाने की तैयारी थी। हिंदी 'केबीसी' को महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं।

हर रोल एक नया चैलेंज लेकर आता है, 'अनुपमा' का किरदार भी कुछ ऐसा ही है

टेलीविजन अभिनेत्री समीक्षा भटनागर इन दिनों टीवी सीरियल 'अनुपमा' में श्रुति आहूजा के किरदार में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री का मानना है कि वे खुशकिस्मत हैं कि उन्हें श्रुति का दिलचस्प किरदार करने और डीकेपी (डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन) प्रोडक्शंस में काम करने का मौका मिला। अभिनेत्री ने कहा, 'टीवी सीरियल अनुपमा पहले से बहुत लोकप्रिय शो है, जब मुझे डीकेपी (डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन) प्रोडक्शंस की तरफ से मुझे श्रुति आहूजा का किरदार निभाने को मिला, तो मैंने सबसे पहले उसे समझा। मुझे लगा कि इसमें दम है और यह मुझ पर सूट करता है। इसी बात ने मुझे जल्दी से रोल करने के लिए मना लिया और अब लोगों को भी यह किरदार पसंद आ रहा है।' अभिनेत्री ने आगे श्रुति आहूजा के किरदार के बारे में बताया, 'हर रोल एक नया चैलेंज लेकर आता है और श्रुति आहूजा का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। वह एक मां है, जिन्हें अपनी बेटी के लिए खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है। वह अपनी बेटी से प्यार करती हैं, लेकिन वह एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं हैं और मैं नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें उस तरह से देखें।'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि स्क्रीन पर उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना एक एक्टर की जिम्मेदारी है।' अभिनेत्री ने आगे बताया कि जब भी उन्हें कोई रोल ऑफर होता है, तो वह पहले अपने किरदार के बारे में सोचती हैं कि उसमें क्या नयापन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'जब भी मुझे कोई रोल ऑफर होता है, तो मेरे लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है कि मैं उस किरदार में क्या ला सकती हूं। एक एक्टर के तौर पर, मैं उसमें क्या योगदान दे सकती हूं? उसके बाद, कैरेक्टर के बारे में मेरी समझ बहुत जरूरी हो जाती है। मेरे लिए स्क्रीन पर रोल के साथ जस्टिस करना और यह पक्का करना भी उतना ही जरूरी है कि लोग उससे कनेक्ट करें।'

सलमान खान 'मॉन्स्टर' के लिए खुद करेंगे जोखिम भरे स्टंट्स

सलमान खान और नयनतारा की एक्शन फिल्म का नाम 'मॉन्स्टर' तय माना जा रहा है। अभी तक फिल्म को अस्थायी तौर पर 'SVC 63' के नाम से जाना जा रहा था। हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी तक टाइटल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सलमान की इस फिल्म को को बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस और काफी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। इसी बीच सेट से खबर आई है कि सलमान के बॉडी डबल को अचानक हार्ट अटैक आ गया। इसके बावजूद शूटिंग की रफ्तार न थमे, इसलिए उन्होंने खुद ही जोखिम भरे स्टंट्स करने का फैसला लिया है। सलमान शूटिंग को लेकर बेहद गंभीर हैं और नहीं चाहते कि किसी भी वजह से काम अटक। हालांकि, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम में नए स्टंट एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जा रहा है।

हेली शाह ने खुद में खोजा कॉमेडी का एक नया पहलू

टेलीविजन और ओटीटी पर अपने दमदार अभिनय के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री हेली शाह अपनी आगामी वेब सीरीज 'चुंबक' के साथ पहली बार कॉमेडी करती नजर आनेवाली हैं। हालांकि इस संदर्भ में हेली का मानना है कि इस नए जॉनर को एक्सप्लोर करना उनके लिए उत्साह के साथ-साथ घबराहट से भरा अनुभव भी था, लेकिन शो के राइटर-डाइरेक्टर आतिश कपाड़िया के विश्वास और भरोसे ने उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने और अपने अभिनय के एक ऐसे पहलू को खोजने में मदद की, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं आजमाया था। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए हेली ने कहा, 'यह पहला मौक़ा है जब मैं कॉमेडी कर रही हूं। मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं की। और मैं सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं इसे कर पाऊंगी। सच कहूँ, तो अब मुझे लगता है कि यह अतिश सर का मुझ पर भरोसा और विश्वास ही था कि मैं यह कर पाई। मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने मेरे अंदर वह चमक देखी, क्योंकि मैं सच में सेट पर खुद को पूरी तरह सरेंडर करके गई थी। मुझे नहीं पता था कि यह कैसा होगा और मैं क्या करूंगी।'

गौरतलब है कि हेली के लिए यह अनुभव सिर्फ एक नए जॉनर को आजमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके लिए अपने अभिनय के एक अनदेखे पहलू को खोजने का मौका भी बन चुका है, जिसमेंआतिश कपाड़िया ने उनकी मदद की। इस सिलसिले में हेली कहती हैं 'उन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर मुझे अपने एक ऐसे हिस्से को एक्सप्लोर करने में मदद की, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं कॉमेडी भी कर सकती हूं। और इसके लिए मैं सर की बहुत आभारी हूँ।'

क्या साथ नजर आएंगे करीना और धनुष?

संजय लीला भंसाली एक पौराणिक जंगल एडवेंचर फिल्म बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें करीना कपूर खान नजर आएंगी। उनके अलावा साउथ एक्टर धनुष भी लीड रोल में होंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान पीएस मित्रन संभालेंगे। हाल ही में मिथ्रन ने फिल्म को लेकर अपडेट शेयर किया है। निर्देशक पीएस मित्रन ने बताया कि संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनने वाली एक फिल्म के लिए करीना कपूर खान और धनुष के साथ बातचीत चल रही है। पीएस मित्रन इन दिनों 'सरदार 2' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस दौरान 'सिनेमा विकटन' से बात करते हुए मित्रन ने कहा, 'करीना और धनुष से बातचीत चल रही है, हम कन्फर्मेशन के लिए तारीखें देख रहे हैं। उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा'। मित्रन के इस अपडेट के बाद भंसाली के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म के लिए करीना और धनुष के साथ आने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है।

इसी साल शूटिंग शुरू होने की उम्मीद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाए जाने की तैयारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट अभी लिखने के स्टेज पर है और फाइनल होने से पहले इसकी स्क्रिप्ट को कई बार फिर से लिखा गया है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवंबर 2026 में प्री-प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, जनवरी 2027 में मुख्य शूटिंग की योजना है। अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, तो यह हिंदी सिनेमा में मित्रन के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म होगी। इसी के साथ इस फिल्म में धनुष और करीना कपूर खान पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। वहीं, 2000 के दशक की शुरुआत में मनमुटाव के बाद संजय लीला भंसाली के साथ करीना इस फिल्म में पहली बार काम करेंगी।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अनुज कुमार के द्वारा एजीएस पब्लिकेशंस एफ 23, सेक्टर 6, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 से मुद्रित व गांव बुखारीपुर, पोस्ट ढवारसी, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश पिन कोड 244242 से प्रकाशित।
संपादक-अनुज कुमार, R.N.I. No.-UPHIN/2023/86483, मो0.945688 4327, E-mail-officialsabkasapna@gmail.com, www.sabkasapna.com नोट- समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र अमरोहा जनपद न्यायालय होगा।